PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) BILL

LAID ON THE TABLE AS PASSED BY RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I lay on the Table of the House the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Bill, 1958, as passed by Rajya Sabha.

12.12 hrs.

RESOLUTION RE: SUGAR EXPORT PROMOTION ORDINANCE AND SUGAR EXPORT PROMOTION BILL

Mr. Speaker: The House will now take up discussion on Shri Braj Raj Singh's resolution regarding disapproval of the Sugar Export Promotion Ordinance, 1958, and the Sugar Export Promotion Bill, 1958.

The resolution and motion for consideration of the Bill will be discussed together after which the resolution will be put to the vote of the House first and, if negatived, the motion for consideration of the Bill will be put to the House.

As the House is aware, five hours have been allotted for both the items

I will first allow the resolution to be moved and then, after it is placed before the House, the motion for consideration of the Bill will be moved. Then there will be discussion on both these motions by the Members of the House.

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव लोक-सभा के विचार के लिये पेश करता हूं :

> "यह सभा २७ जून, १९५८ को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित चीनी निर्यात संवर्द्धन अध्यादेश, १९५८ (१९५८ का अध्यादेश संख्या ५) को नामंजूर करती है ।"

श्रीमन्, सदन के माननीय सदस्यों को और देश के बहुत से नागरिकों को यह जानकर कि मैं इस आर्डिनेंस की नामंजूरी के लिये प्रस्ताव पेश कर रहा हूं बहुत सी गलतफहमी पैदा हो सकती है । यह कहा जा सकता है कि मैं आर्डिनेंस की इस भावना के विरोध में हूं कि कोई भी चीनी देश से बाहर भेजी जाये । लेकिन मैं शुरू में ही, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह प्रकट कर दूं कि जहां तक चीनी के निर्यात का सवाल है, जहां तक देश की विदेशी विनिमय की समस्या को हल करने का सवाल है, फारिन एक्सचेंज अर्न करने का सवाल है, वहां तक मैं बिल्कुल सरकार के साथ हूं । मैं चाहता हूं कि अगर देश की किसी भी वस्तु से विदेशी विनिमय पैदा किया जा सकता है तो ज्यादा से ज्यादा इसके लिये कोशिश की जानी चाहिये और उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट बरदास्त नहीं की जानी चाहिये । मेरा इस प्रस्ताव को पेश करने का उद्देश्य यह नहीं है कि चीनी का बाहर को एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिये । मैं यह नहीं चाहता कि चीनी का निर्यात न किया जाये लेकिन मेरा इस अध्यादेश के विरोध से दूसरा उद्देश्य है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को उस समय लागू करके, जब कि लोक-सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा था, सरकार ने जान में या अनजान में हिन्दुस्तान के उन लोगों का जो कि चीनी का उपयोग करते हैं करोड़ों रुपये का नुकसान कर दिया । यदि इस अध्यादेश के बजाय लोक-सभा के पिछले अधिवेशन में जब कि अधिवेशन चालू था, यह बिल लाया गया होता जो कि अब हमारे सामने अध्यादेश के बजाय पेश किया जा रहा है, या जून २७ को इस अध्यादेश को जारी करने के बजाय लोक-सभा के अगले अधिवेशन में यह बिल लाया गया होता और थोड़ा इन्तिजार कर लिया गया होता तो हिन्दुस्तान के उन लोगों का जो चीनी के उपभोक्ता हैं करोड़ों रुपये का नुकसान न हुआ होता, ऐसा मेरा विचार है ।

मैं अपनी इस बात को आंकड़ों से साबित करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से इस अध्यादेश के जारी होने से हिन्दुस्तान के चीनी कारखाने वालों ने नाजायज तरीके से चीनी के उपभोक्ता से वैसे वसूल किये और हमारी जनप्रिय सरकार एक दर्शक मात्र बनी रह गयी । मैंने २६ जुलाई को यह प्रस्ताव लोक सभा में पेश करने का नोटिस दे दिया था । उसी समय सरकार जागी और उसने ३० जुलाई को नोटीफिकेशन द्वारा चीनी की कीमतें निश्चित की ।

आप देखेंगे कि चीनी के उद्योग को हिन्दुस्तान में सभी उद्योगों से अधिक संरक्षण दिया गया है । इस उद्योग को १५ साल तक संरक्षण दिया गया और इस तरह से हिन्दुस्तान के चीनी उपभोक्ताओं ने करोड़ो रुपये की कुर्बानी करके चीनी उद्योग को पनपाया । लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो आपको पता चलेगा कि चीनी के मिल मालिको ने हिन्दुस्तान के उपभोक्ता की, और किसान की जो कि गन्ना पैदा करता है, तथा हिन्दुस्तान की सरकार की जो कि हमारी प्रतिनिधि है, कोई परवाह नहीं की । मिल मालिको का उद्देश्य यही रहा कि किसी तरह से ज्यादा से ज्यादा पैसा पैदा करे । और अपना मुनाफा कमायें और इस तरह से सब लोगो के हितों का हनन करे । यह जो १५ साल का संरक्षण दिया गया और उसके कारण जो कुछ चीनी उद्योग का उत्थान और विकास हुआ इसका श्रेय केवल चीनी के मिल मालिको को ही नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो पता चलेगा कि यह संरक्षण देने में जनता ने करोड़ो रुपये का नुकसान उठाया है । एक जमाना जब कि हिन्दुस्तान में बाहर से सस्ते दामों पर चीनी आ सकती थी और उस समय हमारे लिये विदेशी विनिमय की भी कोई कठिनाई नहीं थी, उस वक्त संरक्षण देकर हमने इस उद्योग को पनपाया और इस तरह से हिन्दुस्तान के लोगों की करोड़ों रुपयों की हानि की जो कि बच सकती थी । आप देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से चीनी के मिल मालिकों ने अधिक से अधिक मुनाफा कमाया है । सरकार द्वारा प्रकाशित "Sugar in India 1955-56" के सप्लीमेंट में टेबिल नम्बर ४१ को आप देखें जिसका हेडिंग है "Sugar Industry—Chain Index of Industrial Profits". इस टेबिल में १९३९ को सौ का बेस मान कर शुगर इंडस्ट्री की दूसरे उद्योगों से तुलना की गई है । इसको देखने से आपको मालूम होगा कि सन् १९३९ को सौ का बेस मान कर सन् १९५३ में शुगर उद्योग का प्राफिट ४१९ ८ था जब कि दूसरे उद्योगों का मुनाफा २६१ २ था, १९५२ में शुगर इडस्ट्री का प्राफिट ४०९ ८ था जब कि दूसरी इंडस्ट्रीज का १९० ६ था, इसी तरह से १९५४ में शुगर इडस्ट्री का प्राफिट ३३४ ९ था जब कि दूसरे उद्योगो का ३१४ २ था । इतना होने पर भी जब हमारे खाद्य मंत्री इस उद्योग के अखिल भारतीय अधिवेशन में भाषण देने गये तो वहा पर उनसे कहा गया कि हमारे ऊपर इतना टैक्स लगा हुआ है, चीनी पर १३ रुपये तीन आने मन टैक्स लगाया गया है, अगर आप इस टैक्स को कम करें तो हमारा प्राफिट बढ़ सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी आकड़ो से यह प्रकट है कि हिन्दुस्तान में और किसी उद्योग ने इतना लाभ नहीं कमाया है जितना कि शुगर इंडस्ट्री ने कमाया है, और फिर भी अगर सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, या केन सैस लगाया जाता है, या कोआपरेटिव सोसाइटीज के लिये कुछ कमीशन टैक्स लगाया जाता है, तो चीनी के मिल मालिक होहल्ला मचाते हैं और कहते है कि हम दबे जा रहे हैं, टैक्स कम करो । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो चीनी उद्योग पर टैक्स लगाया गया है मैं उसका शतप्रतिशत समर्थक हूं । मैं निवेदन करूंगा कि यदि देश के विकास के लिये इस तरह के

[श्री ब्रजराज सिंह]

उद्योग पर अधिक टैक्स लगाया जाये तो वह स्वागत योग्य है । किसी मिल मालिक के विरोध की वजह से सरकार को इस टैक्स को कम करने की बात नहीं सोचनी चाहिये ।

इसी के साथ साथ आप देखें कि चीनी उद्योग के मिल मालिक एक और बात कहते आ रहे हैं गुड़ और खंडसारी के बारे में । वे कहते हैं कि खंडसारी पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाओ । यह छोटा, गृह उद्योग है, जिसको हम अपनी नीति के मुताबिक पनपाना चाहते हैं । इसका विकास और उत्थान सरकारी संरक्षण के आधार पर किया जाना चाहिये और किया जा रहा है । परन्तु ये चीनी के मिल मालिक इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि खंडसारी पर भी टैक्स लगाओ जिससे चीनी का उद्योग अधिक पनप सके ।

इसी संदर्भ में मैं यह दिखाना चाहता हूं कि चीनी का उत्पादन किस प्रकार बढ़ा है । आप देखें कि सन् १९४८–४९ और सन् १९५६–५७ के बीच चीनी का उत्पादन हिन्दुस्तान में किस तरह से बढ़ा है । सन् १९४८–४९ में चीनी का उत्पादन देश में १०,०५,६६९ टन था जब कि सन् १९५७–५८ में वह २०,२६,१७९ टन हो गया । सन् १९५५–५६ में यह १८,६१,८३७ टन था । इसी तरह से दूसरे सालों में है । इस साल के सम्बन्ध में सरकार का अनुमान है कि देश में चीनी का उत्पादन १९,७५,००० टन के करीब होगा । इस तरह से सरकार की कृपा से संरक्षण के कारण जो इस इंडस्ट्री को मिला और किसान के प्रयत्न के कारण जो कि गन्ना पैदा करता है, इस इंडस्ट्री का उत्पादन बढ़ा है । किसान के दाम गन्ने के कम थे । पर पिछले दिनों यानी सन् ४९ में यहां पर लेजिसलेटिव असेम्बली में चीनी के बारे में बहस हुई उसके बाद सरकार ने गन्ने का भाव बढ़ा कर १ रुपया १२ आना मन कर दिया था । यानी रेल सेंटर पर १ रुपया १२ आना तथा दो रुपया तक दाम दिया गया । लेकिन जैसे जैसे चीनी के मिल मालिक संगठित होते गये और सरकार पर हमला बोलने लगे, वैसे वैसे हम देखते हैं कि किसान को कम कीमत दी जाने लगी । अब उसको १ रुपया ५ आना या १ रुपया ७ आना से ज्यादा कीमत नहीं दी जाती है । सरकार से बार बार गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये अनुरोध किया गया । बिहार और उत्तर प्रदेश में गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है इसलिये उत्तर प्रदेश की असेम्बली ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आना मन की जाये, लेकिन हमारी सरकार मिल मालिकों से दब जाती है और गन्ने की कीमत नहीं बढ़ानी जब कि गन्ने का चीनी के उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश के पास करने से क्या गलती हुई ।

जुलाई के महीने में १,७०,००० टन चीनी फ्री सेल के लिये छोड़ी गई । सरकार ने यह मंजूर किया है कि आर्डिनेंस पास होने से पहले ही चीनी की कीमत आर्डिनरी तरीके से एक रुपया, सवा रुपया, डेढ़ रुपया बढ़ चुकी थी । चूंकि बाहर चीनी कम दाम पर बिकती है और यहां ज्यादा दाम पर बिकती है, इसलिये सरकार और मिल मालिक यह मंजूर करते हैं कि बाहर जो ५०,००० टन चीनी भेजी जायेगी, उस पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान ८ आने प्रति मन पड़ेगा । आर्डिनेंस के बाद जो प्रेस नोट जारी किया गया, उसमें कहा गया कि ८ आने प्रति मन से ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता है । सरकार यह जानती थी कि मिल-मालिक आर्डिनेंस के पास होने से पहले ही रुपया, सवा रुपया

प्रति मन चीनी की कीमत ज्यादा वसूल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उसने चीनी की कीमत निश्चित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार की ओर से यह कहा गया कि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि चीनी की कीमत बढ़े, बल्कि वह चाहती है कि चीनी की कीमत स्टेबिलाइज हो और कम हो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि २७ जून से ३० जुलाई तक चीनी की कीमत बढ़ती रही और सरकार अपाहिज की तरह सब कुछ देखती रही और उसकी ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस बीच में मिल-मालिकों ने करीब करीब १,७०,००० टन चीनी औसतन दो रुपये प्रति मन ज्यादा के हिसाब से बेची—उन्होंने १ रुपये से लेकर साढ़े तीन रुपये प्रति मन बढ़ा लिये थे और अगर मोटे हिसाब से देखा जाये, तो वह वृद्धि दो, ढाई रुपये के हिसाब से पड़ती है—और इस प्रकार ६३ लाख रुपये का अतिरिक्त मुनाफा पैदा किया। इसके बाद भी चीनी की कीमत तय नहीं की गई। १९५७ के बजट में एक्साइज ड्यूटी को दुगुना किया गया था। अगर उसके हिसाब से चीनी की कीमत बढ़ाई जाती, तो किसी भी सूरत में चीनी की कीमत कारखाने से निकलने के समय ३८-८-० रुपये से ज्यादा न पड़ती। जब ३० जुलाई को नोटिफिकेशन के जरिये चीनी की कीमत तय की गई तो क्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में ३६ रुपये प्रति मन और पंजाब में ३६-८-० रुपये प्रति मन चीनी की कीमत तय की गई? ३१ जुलाई, १९५८ को, जब कि ३० जुलाई को जारी किये गये नोटिफिकेशन में चीनी की कीमत निश्चित की जा चुकी थी, मैं समझता हूं स्टाक में ८,७८,००० टन चीनी थी। पहले हमने चीनी के मिल-मालिकों को एक, सवा, डेढ़ रुपया प्रति मन के हिसाब से चीनी की कीमत बढ़ाने का मौका दे दिया, जिससे उन्होंने अतिरिक्त मुनाफा कमाया। ढाई करोड़ रुपये का और अतिरिक्त मुनाफा आप मिल-मालिकों को देने जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही ६३ लाख का अतिरिक्त मुनाफा कमाया था और ढाई करोड़ का और मुनाफा कमाया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि हमने यह आर्डिनेंस जारी करके मिल-मालिकों को तीन करोड़ का मुनाफा दे दिया। अगर सरकार २६, २७ जून, को यह आर्डिनेंस जारी न करके यह सोचती कि शीघ्र ही लोक सभा का अधिवेशन होने वाला है, उसमें इस सम्बन्ध में इस बिल को पेश करेंगे, जिस पर इस सदन के माननीय सदस्य विचार करेंगे और उनके सामने सारी स्थिति आयेगी और उनको पता लगेगा कि क्या हो रहा है तो मैं समझता हूं कि उपभोक्ताओं का जो इतना रुपया ठगा गया है, वह बच जाता और इस प्रकार तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपये की बचत हो जाती।

इस सदर्भ में यह भी जानने की जरूरत है कि हम जो पचास हजार टन चीनी निर्यात करने जा रहे हैं, उसके द्वारा हम कितना फारेन एक्सचेंज पैदा कर सकेंगे। मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि मैं मूलतः उस से सहमत हूं और चाहता हूं कि यहां से चीनी बाहर जाय, जिस से हम फारेन एक्सचेंज पैदा कर सकें और उस के द्वारा हमारे यहां मशीनरी और दूसरा आवश्यक सामान आये। मैं यह भी समझता हूं कि इसके लिये हमको हर संभव कोशिश करनी चाहिये। अगर हम सरकारी आकड़ों को देखें, तो हमको पता चलेगा कि जो चीनी हम निर्यात करने जा रहे हैं उससे हम ढाई करोड़ रुपये की फारेन एक्सचेंज पैदा कर सकेंगे—ज्यादा नहीं, सिर्फ ढाई करोड़ रुपये।

Mr. Speaker: The hon Member's time is up.

Shri Braj Raj Singh: I am not saying anything irrelevant. Some substantial things are to be said.

Mr. Speaker: I am not saying that the hon. Member is irrelevant; he is quite relevant I am giving him 20 minutes.

श्री बजराज सिंह : मैं यह निवेदन कर रहा था कि प्रश्न यह है कि क्या हम लोग आर्डिनेंस जारी होने के बाद से लोक सभा के प्रारम्भ होने तक इस ढाई करोड़ रुपये की रकम में से कुछ फ़ारेन एक्सचेंज पैदा कर सके है। १२ या १३ अगस्त को माननीय खाद्य मंत्री महोदय ने एक सवाल के उत्तर में इस सदन में बताया कि अभी तक विदेश को भेजने के लिये सिर्फ सोलह, सत्रह हजार टन चीनी के वायदे हुये हैं और अभी तक एक औंस भी चीनी बाहर नही भेजी जा सकी है। इसका तात्पर्य यह है कि इस आर्डिनेंस के जरिये हम लोग एक पाई भी फारेन एक्सचेज पैदा नही कर सके है। मैं यह पूछना चाहता हू कि अगर आर्डिनस लाने के बजाय लोक सभा का अधिवेशन शुरू होने के बाद कोई बिल लाया जाता, तो क्या नुकसान हो जाता, जब कि हम आर्डिनेंस के बाद और लोक सभा का अधिवेशन शुरू होने तक एक पाई भी फ़ारेन एक्सचेज नही पैदा कर सके हैं और एक औंस भी चीनी बाहर नही भेज सके है। आखिर इस आर्डिनेंस से क्या उद्देश्य सिद्ध हुआ ? आर्डिनेंस तो तभी लागू किया जाता है, जब कि उसके बिना काम नही चल सकता है, लेकिन इस स्थिति में तो उसके बिना काम चल सकता था। खाद्य मत्री महोदय ने बताया कि बाहर चीनी भेजने में कुछ देर लगती है। मै जानना चाहता हू कि कुछ देर लगती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हू कि इस आर्डिनेंस के पास करने की कोई जरूरत नही थी—खासकर ऐसी विशेष स्थिति में जब कि न सिर्फ तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपये का नुकसान चीनी के उपभोक्ताओ को उठाना पड़ा है, बल्कि सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी के सम्बन्ध में १,५४,००,००० रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा और दूसरे तरीके से भी उसको नुक्सान उठाना पड़ेगा। यह नुक्सान तीन करोड रुपये के करीब हो जाता है। हम यह समझना चाहते हैं कि क्या वजह थी कि इस आर्डिनेंस को इस तरह चपचाप लाग कर दिया गया। बहुत पहले से इस बात की चर्चा चल रही थी कि सरकार चीनी का एक्सपोर्ट करना चाहती है। यह अच्छी बात है। तब हवा में यह बात थी कि दो लाख टन के करीब चीनी निर्यात की जायेगी। इससे पहले स्वेज संकट का फायदा उठा कर हिन्दुस्तान ने १,५३,००० टन चीनी पिछले वर्ष बाहर भेजी और उससे १२ करोड़ रुपये फ़ारेन एक्सचेंज पैदा की। यह अच्छा था। लेकिन अब हिन्दुस्तान के चीनी मिल-मालिको ने यह सोचा कि यहां चीनी का उत्पादन बढ़ने लगा है और अगर यह बढ़ता है, तो हिन्दुस्तान के उपभोक्ताओं को हमे कम दाम पर चीनी देनी पड़ेगी। मै यह निवेदन करना चाहता हू कि हिन्दुस्तान में चीनी की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। इस वक्त जो प्रोडक्शन कास्ट है, उसको देखते हुये उसकी कीमत को कम से कम ३२ रुपये पर लाया जा सकता है। जब आप १–५–० रुपया, १–७–० रुपया मन गन्ने के उत्पादको को दें और उनकी कीमत को बढ़ाने के लिये तैयार न हों, तब चीनी की कीमत को इस तरह बढ़ाते जाना किसी भी तरह उचित नही कहा जा सकता है। चीनी का मिल-मालिक कहता है कि चीनी को बाहर भेजना शुरू करो, जिससे हिन्दुस्तान में आर्टिफिशियल स्केसिटी—बनावटी कमी—पैदा हो जाय और उसके परिणामस्वरूप लोग सोचने लगें कि चीनी बाहर भेजी जा रही है, इस तरह यहा चीनी की कमी हो जायेगी, इसलिये हम उसका स्टाक करें और फिर चीनी की कीमतें बढ़ जायेंगी। हिन्दुस्तान के सौ, सवा सौ मिल-मालिको ने हिन्दुस्तान की सरकार को अपने जाल में फंसा लिया है। मैं यह नही कहता कि सरकार ने जान-बूझ कर ऐसा किया है, लेकिन अगर सरकार अपने तमाम अफ़सरो, इतने बड़े पैराफ़रनेलिया, इतने बड़े संगठन के होते हुये भी इतना ज्ञान नहीं रख सकती कि इससे क्या होने वाला है, तो मैं कहूंगा कि उसकी नीयत जो भी हो, लेकिन वह उन लोगों के जाल में फंस गई है और उसने हिन्दुस्तान

के उपभोक्ताओं का नुक्सान किया है और फ़ारेन एक्सचेंज के ज़रिये एक पैसा भी पैदा नहीं किया है। मेरे पास वक्त नहीं है वर्ना मैं दिखलाता कि किस तरह चीनी के मिल-मालिक यह कह रहे हैं कि फ़ारेन एक्सचेंज पैदा करने के लिये नहीं, बल्कि चीनी का उत्पादन बढ़ जाने से जो संकट आने वाला है, उसका मुकाबला करने के लिये चीनी बाहर भेजी जानी चाहिये। जैसा कि हम जानते हैं, पंच-वर्षीय योजना आयोजन के अन्त तक साढ़े बाईस लाख टन चीनी का उत्पादन और हो जायेगा। मुझे विश्वास है कि उससे और ज्यादा हो जायेगा। चीनी के मिल-मालिकों के दिमाग में भी यह बात थी कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जायेगा और अगर उसकी बिक्री हम नहीं करेंगे तो चीनी का उपभोक्ता ज्यादा दाम नहीं देगा। उन्होंने सोचा कि यह बड़ा अच्छा मौका है कि देशभक्ति भी लूट लें और फ़ारेन एक्सचेंज भी पैदा कर लें। सवा दो करोड़ फ़ारेन एक्सचेंज के लिये देशभक्ति लूटना चाहते हैं। देशभक्ति लूटने के लिये हिन्दुस्तान के चीनी मिल-मालिकों ने सोचा कि हिन्दुस्तान से बाहर चीनी भेजी जाये और सरकार उनके जाल में फंस गई। जिस वक्त लोक सभा बैठ नहीं रही थी और उसमें इस विषय पर विचार नहीं हो सकता था, उस वक्त सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की और उसके परिणाम अच्छे नहीं हुये।

इसलिये लगातार एक महीने तक और तीन महीने से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं, बाज़ार में लगातार चीनी का एक प्रकार से संकट पैदा हो गया है। अब तक जो फायदा मैंने बतलाया है वह मिल-मालिकों का ही बताया है लेकिन जो एजेंटस ने फायदा उठाया है, उसका मैं फौरन अंदाज़ा नहीं लगा सकता हूं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार ने २७ जून को आर्डिनेंस जारी करके हिन्दुस्तान के चीनी उपभोक्ताओं के साथ, चीनी के लिये जो किसान गन्ना पैदा करता है, उसके साथ विश्वासघात किया है। जो गन्ने का उत्पादक है और जिसके गन्ने के दाम बढ़ने चाहियें, वे बढ़ाये नहीं जाते हैं। आप ही के आंकड़ों में बताया गया है कि गन्ने के उत्पादन का जो खर्च पड़ता है वह करीब एक रुपया और चार आने मन पड़ता है और आप जो उसको देते हैं वह एक रुपये पांच आने या एक रुपया सात आने मन ही देते हैं। आपने ही इस बात को माना है कि जो उत्पादक है उसको पांच प्रतिशत मुनाफा दिया जाता है। ज़रूरी था कि उसको गन्ने का अधिक मूल्य दिया जाता, लेकिन इस तरह कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

आप चीनी पर एक्साइज़ ड्यूटी भी वसूल करते हैं। किस तरह से हज़ारों मन चीनी आपके अफ़सर बिना एक्साइज़ ड्यूटी लिये हुये बाहर निकाल देते हैं मेरे पास वक्त नहीं है कि इसको मैं बयान कर सकूं। चीनी के दामों के बारे में उपभोक्ताओं के हितों को, गन्ने के उत्पादक के हितों का आपको ध्यान में रखना होगा और इस ओर ध्यान देना होगा कि कहीं कोई गोलमाल तो नहीं हो रहा है। जब कोई गोलमाल होता है तो उसका असर उपभोक्ताओं पर, किसानों पर, देश पर तथा सरकार पर पड़ता है और इन्हीं को नुक्सान उठाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इन सब बातों की ओर सरकार ध्यान दे। जिस प्रकार से खाद्य संकट पर या खाद्यान्नों पर यहां बहस होती रहती है और कई बार बहस हो चुकी है, उसी तरह से कम से कम एक साल में एक या दो बार चीनी के मामले पर भी बहस होनी चाहिये ताकि हम लोग बता सकें कि किस प्रकार के चीनी के जो मिल मालिक हैं वे जनता का शोषण करने पर तुले हुये हैं तथा किस प्रकार जनता को इस शोषण से बचाया जा सकता है। हिन्दुस्तान के उपभोक्ताओं के कारण तथा उनके द्वारा दिये संरक्षण के कारण जिस तरह से चीनी उद्योग का यहां उत्थान हुआ है, उसको देखते हुये बहुत ज्यादा चिन्ता इस विषय में करने की ज़रूरत है।

[श्री इजराज सिंह]

आज भारत में गन्ने के जो उत्पादक हैं उनकी संख्या तीस लाख के करीब है। बार बार यह मांग पेश की गई है कि उनको जो कीमत अदा की जाती है उसको बढ़ाया जाना चाहिये। जब वह एक रुपया बारह आने या दो रुपया की जा सकती थी तो क्या कारण है कि अब इसको एक रुपया पांच आना या एक रुपया सात आना से ज्यादा नहीं किया जाता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अगर आप गन्ने के उत्पादकों को सन्तुष्ट नहीं कर सके और केवल सौ या सवा सौ मिल मालिकों को ही सन्तुष्ट करने में लगे रहे तो आपका काम चलने वाला नहीं है। अब समय आ गया है जब इस ओर भी आपका ध्यान जाय। चीनी के मिल मालिकों का आज तक जो रवैया रहा है वह इस तरह का रहा है कि उससे न देश को लाभ हुआ है, न उपभोक्ताओं को हुआ है और नहीं जो गन्ने के उत्पादक हैं, उनको ही हुआ है। इतना ही नहीं सरकार को भी कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्या अब उचित समय नहीं है कि चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो, तथा इस उद्योग को सरकार अपने कब्जे में ले। यह कहा जा सकता है कि ७२ करोड़ के करीब इस उद्योग में पूंजी लगी हुई है तथा सरकार के पास मिल मालिकों को देने को मुआवजा नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे कारखाने मौजूद हैं जिन्होंने तीन चार सालों के अन्दर ही सारी की सारी पूंजी को, सारे के सारे कैपिटल को बाहर निकाल लिया है और अब उन कारखानों में कोई रुपया नहीं रह गया है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह एल० आई० सि० से भी बड़ा स्कैंडल है। उस समय आपका २५ लाख का नुकसान रहा होगा। यहां पर तीन साढ़े तीन करोड़ का नुकसान उपभोक्ताओं को हुआ है तथा साढ़े तीन करोड़ का नुकसान सरकार का या दूसरी तरह से हुआ है और इस तरह से छः साढ़े छः करोड़ का कुल नुकसान हुआ है। इस बात पे गम्भीरतापूर्वक विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से सन १९४९ में जब कि श्री अजित प्रसाद जैन ही खाद्य मंत्री थे और उनके प्रस्ताव पर ही यह मान लिया गया था कि एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाये, उसी तरह से आज फिर एक इन्क्वायरी कमेटी बिठाई जाये जो सारे मामले की छानबीन करे और छानबीन करके सिफारिशें करे कि आगे के लिये चीनी उद्योग को किन लाइन्स पर चलाया जाये, क्या चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो किस तरह से, जो गन्ने के उत्पादक हैं उनको कितना लाभ हो रहा है तथा क्या उनको उनके गन्ने का और अधिक मूल्य दिया जा सकता है, जो उपभोक्ता है उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जा सकता है तथा किस तरह से कीमतों पर नियंत्रण रखा जा सकता है?

Mr. Speaker: Motion moved

> "This House disapproves of the Sugar Export Promotion Ordinance, 1958 (Ordinance No 5 of 1958) promulgated by the President on the 27th June, 1958."

Now the hon Minister may move the motion for consideration of the Bill. Hon Members will have opportunity to speak on both the Bills as also the Resolution

The Minister of Food and Agriculture (Shri A. P. Jain): I beg to move:

> "That the Bill to provide for the export of sugar in the public interest and for the levy and collection in certain circumstances of an additional duty of excise on sugar produced in India, be taken into consideration."

Mr. Speaker: He may also refer to the points that have been referred to

by the hon. mover of the Resolution. Here I want to know one thing. The previous session went on till about the 11th of May. Why could he not have thought of this measure at that time? Why was this put off till the end of the session? Government should, as far as possible, avoid bringing in Ordinances. If only Government had considered this matter some time earlier, the promulgation of the Ordinance could have been avoided. I hope the hon. Minister will kindly explain this point.

Shri A. P. Jain: I will answer the query raised by you during the course of my speech.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): Let him be a little louder so that we can also hear him.

Shri A. P. Jain: Surely you will hear me.

As hon. Members are aware, when in 1956 Government decided to undertake the export of sugar, the circumstances were very favourable, partly on account of the Suez Crisis and partly because the beet-root crop in Europe had failed. The prices of sugar in the world market were high We actually started the export of sugar in the month of January 1957, and during the course of the year we could export a little more than 150,000 tons of sugar, earning foreign exchange to the tune of about Rs. 12½ crores.

One of the important problems before us at that time was: what was the agency to be employed for effecting this export. After giving due consideration to the various methods of export, we entrusted this work to the Indian Sugar Mills' Association to export on "No Profit; No Loss" basis. All the profits made on account of export are to be funded and a part of it is to be utilized, later on, for meeting the losses when the prices in the world market went down. A part of the profits are there. Here I take the opportunity to thank the Indian Sugar Mills' Association for helping the country by exporting a fairly large quantity of sugar on "No Profit; No Loss" basis.

Then, conditions changed later on and the prices of sugar in the world market went down. Our cost of production is comparatively higher. I will go into the break-up a little later and I shall try to explain the reasons why it is higher than the world prices. Nonetheless it was a fact that while, roughly speaking, our cost of production was about £50 to £52 per ton, the world prices for the British refined sugar were as low as £36 or £37 per ton. Our sugar is somewhat inferior to the British refined sugar, and therefore it fetches £2 or £3 and sometimes £4 less than what the British refined sugar fetches in the world market. We were, therefore, confronted with a rather difficult problem, as to how we could export the sugar.

One of the questions that came before us was whether the Government could subsidise it, and we found that it would invoke the provisions of GATT Therefore, this scheme was discussed at various levels in respect of the agency to be employed, whether we were in a position to export, and if we had to export at a price lower than the ex-factory price, how the difference of the losses were to be met. It was by no means an easy scheme for us, and we spared no time in working out the scheme, but nonetheless it took time, and we could finalise the scheme only after the Parliament had adjourned.

Shri Ranga (Tenali): Very convenient.

Shri A. P. Jain: We could have waited for this session of Parliament That was the alternative left before us, but the House is well aware of our foreign exchange needs, and we therefore thought that we should take the earliest steps to give a legal shape to this scheme. In fact, we also

[Shri A. P. Jain]

examined the question whether we could effect the export of sugar without undertaking law, but we were advised by the Ministry of Law that we could not do it

It is not that no benefit has accrued as a result of the passing of this Ordinance. First, we had to set up the machinery and then in the month of July we entered into a contract for the export of 16,870 tons of sugar. Out of this actually 9,900 tons of sugar have been exported in the month of August. It is, therefore, clear. . . . .

Shri Braj Raj Singh: On which date in August?

Shri A. P. Jain: Up to now, up to the 23rd August.

Shri Braj Raj Singh: I presume that it has been exported after this session of the Lok Sabha began

Mr. Speaker: All exports have taken place only after the Lok Sabha session started?

Shri A. P. Jain: I will find out

Assuming we had not passed the Ordinance, it would have taken some time for the Lok Sabha to pass the Bill. In fact, we introduced it at the very earliest date, and I do not think we could have passed the Bill . . .

Mr. Speaker: We pass the Bill in two hours.

Shri A. P. Jain: Even if it had been passed in two hours, it would have taken us one or two weeks to set up the machinery.

Shri Ranga: It could have been done earlier without having to come to Parliament.

Shri A. P. Jain: We could not do it because the law was necessary. Valuable time would have been lost, while now we have earned some foreign exchange.

I can assure you that the Government is fully aware of the fact that Ordinances should not be promulgated except under very exceptional circumstances, and we did give thought to this question, but we felt that our need for earning foreign exchange was so urgent, and that if we did not pass the Ordinance, we would be losing some time.

Shri Naushir Bharucha: How much foreign exchange have they earned on 9,000 tons?

Shri A. P. Jain: It would be about Rs. 50,00,000.

We started making contracts from the 5th July onwards. The ordinance was passed on the 27th June, and we made our first contract on 5th July and went on making the contracts So, all this time would have been lost At any rate, we could not have functioned in the month of July and up to the 10th of August, and valuable time would have been lost.

Shri Naushir Bharucha: You could export later, send them in a bunch later on.

Shri A. P. Jain: That is the justification for promulgating the ordinance.

There was also another reason. Some rumours had been going about in the market that the Government intended to undertake export, and from the month of April onwards—I believe from the month of May—the prices were showing a little upward trend, and therefore if we had not undertaken the scheme, that upward trend, in fact, would have continued.

Shri Braj Raj Singh: You could control the price.

Shri A. P. Jain: That is what I am coming to, how we controlled the prices.

When we decided to pass the Ordinance, we had consultations with the industry The industry had raised its price by about a rupee, and we felt that the losses on the export could be met out of this rise of Re 1 In fact, roughly we calculated that if the Government decided to export 50,000 tons of sugar, the loss would be about Re. 0-8-0, if on the other hand Government decided to export one lakh tons of sugar, the loss would be about a rupee per maund Therefore we asked the millowners not to raise the ex-factory price of the sugar and they gave us an assurance before this Ordinance was passed Now, some of the millowners complied with that assurance, others did not

Shri Khuswaqt Rai (Kheri) What was the percentage of those complying and not complying?

Shri A. P Jain: Well, I cannot give the percentage

Therefore we thought of some device, and we gave a release of 1,70 000 tons of sugar in the middle of July

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur) Did the Government-owned mills not raise the price? What was their price?

Shri A P Jain The Government owned mills did not raise the price In fact, the Government does not own any mills, they are Government-managed We did not raise the price and some of the Southern mills did not raise the price, some in North India did not raise the price, some mills did raise the price

Then, about 15 days after enacting the Ordinance, we gave a release of 1,70,000 tons and we also asked the millowners that they should freely release and sell the sugar so that this rise might be eliminated. Some of the millowners did not play the game, and they withheld the quota that had been released. We were therefore driven to the necessity of promulgating an Order, and we promulgated the Order on the 30th July

Now, let us look at the sequence of the events The Ordinance was passed on the 27th June, and we took effective steps to control the prices on the 30th July

Shri Braj Raj Singh. After 33 days

Shri A P. Jain: One has to watch the market trends, one has also to apply other devices For instance, we applied the credit squeeze It had some effect, but not the full effect, and ultimately we undertook to control the prices which has had a salutary effect The expected prices today in some places are lower than the controlled prices

Shri Feroze Gandhi: (Rai Bareli): What are the prevailing prices in Delhi?

Shri C D Pande (Naini Tal) The difference between the consumer's price and mill price is Rs 6

Shri Ranga He says that they are lower

Shri A P Jain The ex-factory price is Rs 36 Rs 1 12 - is the octroi and the Delhi wholesale prices are

Shri C. D Pande. Retail price is more important than the wholesale price for us

Shri A P Jain: On the 14th August the Delhi wholesale prices were Rs 38

Shri A. C Guha (Barasat) That is the wholesale price What is the consumer's price?

Shri A. P. Jain: I understand that in some of the shops in old Delhi it is Re -/15/6 and in other shops it is Re 1 It may be Rs 1 - 3 or so in a shop or two

Shri C. D. Pande: Rs 1|1|- is the common price

Shri A. P. Jain: May be, I do not know. But I am giving the old Delhi prices.

12.51 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

Obviously, now the question is: Can the Governmnet absolutely control the consumer's price?

An Hon. Member: What are the prices?

Mr. Deputy-Speaker: This should not be the market where prices should fluctuate in this way.

Shri A. P. Jain: On a rough calculation I think there should be at least 1,50,000 to 2 lakhs, and maybe more, retailers working in small hamlets, in villages, in towns and in cities and I submit in all humility that it is not possible to control them. We have not got the machinery to control the 1,50,000 or 2 lakhs or even more of these retailers. The only way of controlling them is that more and more supplies must be made available in the market and at a price That is what we have done

You will recollect that during the discussion on food a number of complaints were made about the working of the fair price shops Their number is only 40,000 Each of the fair price shop dealer is selected by the Government. There are regular inspectors and even then, I must admit, there have been some cases of irregularity. Have we got a machinery? It is easy to say, but has the Government of India the machinery or have even the State Governments the machinery to control the 2 lakhs or even more of these retail shops situated all over the country from the smallest village to the biggest city of Bombay and Calcutta? We have not got the machinery and I must confess that we cannot control it.

Shri Ranga: Nobody says about controlling them.

Mr. Deputy-Speaker: If nobody says that, then both sides agree.

Shri A. P. Jain: What we have done now is to increase the availability of sugar in the wholesale market and that has an effect. I hope that it will have a further effect of reducing the consumer's prices.

A question has been raised by the hon Speaker who preceded me that the sugar industry has made—how many crores of rupees I do not remember—profit. He quoted some figure.

Mr. Deputy-Speaker: Rs. 2 crores.

Shri Braj Raj Singh: It is Rs. 3 crores in all

Shri A P. Jain: The sugar industry, I dare say with a considerable amount of confidence, is the most regulated industry in India The price of sugarcane is controlled Wages of the labour are controlled

Shri Panigrahi (Puri): What about mill-owners?

Shri A P. Jain: Have a little patience. Running commentaries will not help anybody. I am coming to the millowners. The mnufacture is controlled If there is any extra profit .

An Hon. Member: It is wrong.

Shri A. P. Jain: It is totally right. (*Interruption*)

Mr Deputy-Speaker: Order, order. It is not going to be decided in this manner.

Shri A. P Jain: If there is any extra profit over and above the fair accepted price, that profit is shared in the proportion of about 2 to the canegrower and 1 to the millowner. The formula of the price of sugarcane has been revised in the previous years. The price of sugar cane was Rs. 1/7/- and Rs. 1/8/- by a voluntary

understanding with the industry. A part of the extra profit which the millers earned was paid to the growers as bonus. Now that position has been altered and the statutory position today is that the price of the sugarcane is Rs. 1/5/- or Rs. 1/7/-, as it may be, whether the supply is at the gate or at other places plus the bonus, which is now a part of the price. Any extra profit which a millowner makes over and above the specified price is shared in the proportion of about two to the cane-grower and one to the millowner.

Now I come to the break-up of the price of sugar. On the basis of all-India figures, out of every hundred rupees that are earned by the sale of sugar, the sugarcane grower gets Rs. 40·40 nP, the taxes, i.e., cane cess, excise duty, co-operative societies' commission, are Rs. 36·50 nP, manufacturing charges and rehabilitation allowance are Rs. 17·60 nP, allowance for loss of export is Rs. 1.40 nP. The millowner gets Rs. 2·70 nP out of Rs. 100 as profit.

Shri Jhunjhunwala: Is it 50 nP or 15nP?

Shri A. P. Jain: There are other provisions. (*Interruption*)

Mr. Deputy-Speaker: The hon Member may differ. But the time of criticism will come when the speech has been delivered.

Shri A. P. Jain: I want the hon. Members to challenge these figures and say that they are wrong.

Shri Jadhav (Malegaon): May I bring to the notice of the hon. Minister that Shri Kasturbhai Lalbhai has made a statement that sugar millowners get a profit of 10 per cent.

Shri A. P. Jain: I do not know what he has said and on what authority he has said that, but the all-India figures are that the profit is 2·7%, or on Rs. 100 the profit is Rs. 2·70 nP. Other miscellaneous allowances are of the order of Rs. 1·40 nP.

It is clear that there is not much elasticity in the price of sugar. If a millowner earns more than Rs. 100 then any money which he earns in excess of Rs. 100 is shared in the proportion of about 2 : 1 by the cane-grower and the millowner. So, I have not been able to appreciate as to how the hon. Member who preceded me has collected his figures and what is the basis of his figures.

Shri Braj Raj Singh: From your figures.

Shri A. P. Jain: There is another evidence and that, I think, is perhaps the most forceful evidence. We have been undertaking a programme for expansion of sugar industry and there are also programmes for the expansion of other industries—cement, jute, textiles, etc. Out of 55 new factories which we licensed, as many as 38 were the co-operative factories and private enterprise was not given . . .

Shri Braj Raj Singh: How many have begun working?

Shri A. P. Jain: Among whom?

Shri Braj Raj Singh: Among the 37 co-operatives.

Shri A. P. Jain: About 12 or 13 and others are coming up.

Now the position is that the sugar industry is not attracting much capital. In fact, Sir, some people who got the licence have not proceeded with the setting up of the sugar mills. I have given the facts; I really cannot understand how the hon. Member makes out that all these extraordinary profits are being made. If a mill works well, it makes more profits; if it works in a bad way it suffers loss. This is the average which the industry is making.

13 hrs.

Now there is no difference of opinion between the hon. Member who has preceded me and the Government that export of sugar is desirable. For the

[Shri A. P. Jain]

time being, we have only fixed a modest quota of 50,000 tons out of which more than 21,000 tons has either been exported or contracted to be exported.

An Hon. Member: How much has been exported?

Shri A. P. Jain: 9,900 tons, a little less than 50 per cent of the contracted export.

The scheme of the Act is something like this, that Government will fix quotas of export from time to time. The aggregate of these quotas will be distributed *pro rata* on the mills in the proportion in which they produce sugar. Each of these mills will be under a statutory obligation to supply that quantity of sugar for export purposes to the exporting agency. If any of the mills commits a default then in addition to the normal excise duty they will have to pay a penal excise duty of Rs. 17. That is, if a mill undertakes to supply the quota it will have to pay no excise duty which is about Rs. 10 and a few annas. If a mill fails to supply the fixed quota not only will it have to pay Rs. 10 and a few annas, but also in addition to that Rs. 17 more as penal excise duty.

Mr. Deputy-Speaker: On the quantity produced or not produced?

Shri A. P. Jain: On the quantity fixed and which was not supplied to the exporting agency.

If the sugar is of the requisite quality which is wanted in the world market the exporting agency will export that sugar. If, on the contrary, the quantity supplied is not of the requisite quality, it will be open to the exporting agency to sell it internally and out of the proceeds buy exportable sugar. Now the price paid to the factories would be the price realised by the sale of sugar in the world market less the expenses. That is the reason why an export a loss will be suffered.

The question of the agency was an important thing. We thought of the various agencies. We thought of the State Trading Corporation. We also thought of setting up a new agency. We also thought of the Indian Sugar Mills Association who I must again repeat have done a good job by exporting a substantial quantity of sugar on no-profit no-loss basis.

Shri Braj Raj Singh: Say three times.

Shri A. P. Jain: Why does it hurt you?

Now, Sir, the State Trading Corporation frankly confessed that they have no experience of the export of sugar and they were not in a position to undertake it immediately. They will have to build up an organisation; so, there will be inevitable delay. The establishment of new agencies would also have meant delay and, therefore, we have entrusted this work of export to the Indian Sugar Mills Association who are not going to make any profit on it and who will act under law. The scheme which we have worked out has been formulated after a great deal of thought and is a practical scheme. We want to export and therefore let us employ an agency which has the experience and which can arrange exports.

With these words, Sir, I commend this motion for the consideration of the House.

Shri A. C. Guha: What is the agency at present?

Shri A. P. Jain: The Indian Sugar Mills Association.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

> "That the Bill to provide for the export of sugar in the public interest, and for the levy and collection in certain circumstances of an additional duty of excise on sugar produced in India, be taken into consideration."

The time allotted is five hours for both. If this Resolution is negatived, then we shall have to spend some time for the second and third stage of the Bill also.

Shri Braj Raj Singh: Only twenty minutes.

Mr. Deputy-Speaker: We might put an hour for that, and four hours for the consideration stage.

Shri Naushir Bharucha: I do not know whether you would extend the time-limit by an hour. This is in your discretion

Mr. Deputy-Speaker: Discretion should not be used for extending the time in every case.

Shri Braj Raj Singh: I was in the Business Advisory Committee The subject is of great importance and so the time should be extended

Mr. Deputy-Speaker: Would hon Members like to sit up to six then?

Some Hon. Members: No, no

Mr. Deputy-Speaker: Let us proceed, I do not promise just at present

Shri Ranga: Mr Deputy-Speaker, Sir, at the very outset I would like to express my dissatisfaction with the means adopted by the Ministry in placing this proposal before the country and this Parliament I wish they had avoided the means of an Ordinance. It places the House in a very embarrassing situation. The House is obliged to discuss this matter presented to us in the shape of this Bill as more or less a *fait accompli*, and we have very little freedom to make the necessary changes in it, whether we consider it to be urgent or not. That is one of the reasons why I feel very strongly over this matter. I do trust that at least in regard to the future, this Ministry will take sufficient care to see that it does not pursue this particular means in order to approach the House.

The reasons given by my hon. friend for having resorted to this are not convincing so far as I can see. They could have taken the necessary steps in building up the machinery and all the rest of it without having to depend upon an Ordinance, and after everything was ready they could have come to this House. Or they could have hastened consultations and confabulations in order to be able to place this Bill before Parliament before the recess Neither of these courses was followed by them It is very difficult to resist the impression that they simply followed the course of convenience For whose benefit? It is difficult to say

Coming to the Bill itself, I find, first of all, the hon Minister has taken it for granted that the House must be unanimously in favour of this general proposal that we should be willing to export sugar under the circumstances and under the conditions when they consider to be necessary, that is, to sustain loss and heavy losses too I am not in favour of that There are two propositions here It is very strange indeed We are importing foodgrains and selling them here at prices higher than prices prevailing in our country, selling them at a loss Now, we want to export sugar and sell it in other countries at a loss. What is this jugglery? Is there any reason behind it? Is there any excuse behind it? It is difficult for me to give an affirmative answer.

Secondly, we are encouraging our own producers to transfer areas of land from foodgrains to commercial crops among which sugarcane occupies a pride of place. In that way, we are running the risk of having less and less produced in this country, and becoming more and more dependent upon food imports Then, we have assured ourselves that we are going to be surplus in sugar What are we going to do with that surplus? We are going to sell it at a loss, and at a heavy loss too. Is it good economics? Is it good planning for our country? I would like my hon friend to recon-

[Shri Ranga]

sider this matter. Even though he may go away with this Bill passed as an Act and all the rest of it, it is never too late to reconsider such an essential matter as this.

Thirdly, here is an area, Bihar and Bengal which are suffering today from food deficits which have to be subsidised as it were by food exports from other areas in that particular zone. The producers of foodgrains in the other areas have got to go with lower and lower prices for their foodgrains in order that they may be made available to the consumers in the deficit areas, in the drought affected areas, in the flood affected areas of U.P. and Bihar at prices which would be within the means of the consumers. Who loses? The producer of food loses, both in the U.P. and Bihar and in other parts of that particular zone. For whose benefit? For the benefit of those consumers including sugarcane-growers also. Why should it be done? Because production of sugarcane is more profitable in these sections and therefore, they should be encouraged. Then, they should be pampered also by the sale of foodgrains to these people at subsidised prices as it were: not actually subsidies, but at prices which would be within their means. Therefore, these prices are being kept down. Is that reasonable, I would like to know.

Then, are we quite sure that we are going to be in possession of these sugar exports for a long time to come? Is it not a fact that only four years ago or five years ago, the Government came to both the Houses with their Bill for the promotion of export of rice? Some of us told them that they were too optimistic. They did not listen to us. They preferred to depend upon their own experts. Now, what is the position today? Have we got food exports? Have we got rice surpluses? What has happened to that particular Act? How much do they say that we would be in surplus in sugar production?

Shri A. P. Jain: Which is the Act that the hon. Member is referring to?

Shri Ranga: That was the Act your Ministry had piloted. I think you piloted it in order to enable the Government to allow rice exports.

Shri A. P. Jain: No, no.

Shri Ranga: If you are not aware, I can only enlighten you later on in the lobbies by going into the Act itself.

Shri A. P. Jain: Enlighten yourself first.

Shri Ranga: I was myself present in the Rajya Sabha. I spoke on that particular subject when it came up before the House. You wanted power to export it from Bengal only. We wanted Government to give freedom to export if we have got surpluses from the South also.

Shri A. P. Jain: Let us be certain.

Shri Ranga: The hon. Minister may ascertain himself whether he is giving . . .

Shri A. C. Guha: Such a proposal came before the House and Government took the consent of the House.

Shri A. P. Jain: Was there a Bill?

Shri A. C. Guha: May be a Bill or something else, I am not sure.

Mr. Deputy-Speaker: It may not be a Bill; it may be in some other form.

Shri Ranga: Whichever the form, does not matter. It came before the House, it was debated upon and passed. The difficulty is, the Ministry is omniscient. We are ignorant and we are obliged to confess ourselves to be ignorant when the Ministry prefers to forget what it has done. That is the plight to which we have been reduced.

Where is the guarantee that we would be able to go on producing this surplus? Have the Government assured themselves of the rising production

of sugar in our country and we would be certainly in a surplus for a period of years? On what authority have they been able to assure themselves? On what assurance? Some assurance there can be if they are able to raise the productivity of the area under sugarcane, if they are able to increase sugar content of the sugarcane. It means this. First of all, they have to assure themselves of the greater raising efficiency of the sugar mills to extract more and more sugar, that the improved sugarcane is such a good thing that the sugar content is going to be on the increase or at least it would be maintained as high as possible and that the pest control and pesticides and all the rest that they have are so perfect that there would be no danger of sugarcane production itself going down or the sugar content itself being reduced. They have got to assure themselves on all these three counts. I do not know whether they have done so and under what authority. What experts have given that particular assurance and that advice?

In addition to that, they can certainly do one thing, that is, by transferring area under foodgrains over to sugarcane. Is that going to be good for the country, I would like to know. Is the need of the country for foreign exchange so great as to turn your lands from food crops to sugarcane? To that, they have got to give a positive answer based upon facts. I cannot be expected to give an answer because I am not in possession of all the facts. One thing is clear. It is bad economics to try to earn foreign exchange by selling your things at dead cheap prices, heavily cheap prices and then to waste foreign exchange by importing food into this country merely because America has been good enough to sell us their surplus foodgrains under that P.L. 480.

Shri C. D. Pande: I do not think it is meant to be paid later on.

Shri Ranga: There is the question of this agency. My hon. friend says here is the Indian Sugar Mills Association, they have done a good job when they were asked to sell on a no-profit no-loss basis, they have gained some experience and therefore, we can continue to utilise them. If they have had experience, we could expect them to lend their experts to our State Trading Corporation. The State Trading Corporation, after all, has been doing some business. Surely, the Government cannot mean to say that the State Trading Corporation is not good enough to do any kind of trade, because, they have been doing some trade all these four years. They have themselves spoken in praise of it. If you want to supplement it, invite the experts of the Indian Sugar Mills Association to come and help them and assist them and supplement their efforts. In that way, why should not the Government think in terms of making use of the State Trading Corporation?

There is the other question of making profits. According to my hon. friend, the manufacturers do not seem to be making great profits and in fact it is only 8 per cent. He said that the millowner is only getting Rs. 2·70—I do not know—I am prepared to accept his figure.

Shri C. D. Pande: Per Rs 100. That is a different thing.

Shri A. P. Jain: Per Rs. 100.

Shri A. C. Guha: Percentage on the invested capital: that is the main point.

Shri Ranga: It has got to be very carefully examined. On every Rs. 100 that goes into the purchase of sugar, this man gets only Rs. 2·70. That means that he is getting it on all the investment being made by the cane-growers, on all the investment being made by the wholesalers and all the retailers and everybody else in this country. The cane-growers are getting Rs. 40.40.

Shri Braj Raj Singh: That is cane price.

Shri Ranga: He says that that is the only portion which the grower is getting. In terms of profits, how much does it work out to? He has not been good enough to tell us.

My hon. friend Shri Braj Raj Singh has given us some figures of the rate of profits that these sugar merchants or mill-owners have been making.

Shri Braj Raj Singh: I challenge him to contradict them.

Shri Ranga: He says that he has taken it from Government publications Therefore, I would like my hon. friend to say that it is not correct, and they are getting something else; I am not bothered about it, because I am not on that point now that the sugar mills are making so much of profits and that they should not make such profits or anything like that Just now, I am not on that point My point is just this My hon friend wanted us to feel assured or feel satisfied that the cane-growers are also getting something, that, indeed, the cane-growers are getting twice as much as the mill-owners from out of the surplus that is found after allowing a fair price to the cane-growers I would like my hon. friend to assure me that this particular bonus is being paid in every State to all the cane-growers right up till now. I would like him to tell me whether it is not a fact that in Andhra Pradesh and even in certain parts of Bihar and U.P. also, the payment of this bonus is being delayed on one account or another, that there are questions raised as to how much is to be paid to the growers and so on, and, therefore, the growers are placed at the mercy of the mill-owners.

Then, the other point is whether the manufacturers are going to be benefited by this export or not. There is an impression that they are going to be benefited. There is also the impression that they have benefited. I do not know the facts. I would like my hon. friend to assure the House that the mill-owners are not going to be benefited as a result of this particular policy of exporting sugar to other countries, not only directly, but also indirectly. Does he not give them an opportunity of raising the local price in our own country, directly or indirectly?

Shri A. P. Jain: We have controlled the ex-factory prices.

Shri Ranga: My hon. friend says he has controlled the *ex*-factory prices. I am glad that he has taken that particular step At the same time, is it not a fact that a large number of these sugar mill-owners are having their control over these wholesalers?

Shri Panigrahi: Yes.

Shri Ranga: Quite a good number of them have their own agents also. Have they not themselves built up that particular machinery? Do they not have their fingers in the pie? I agree with my hon friend, and I am not at all in favour of controlling the retail prices, or what is called controlling the retailers. Nevertheless, we would like to know what steps Government have been able to take in order to see that these mill-owners do not play any kind of a prank or trick or whatever it is through their own agents

Shri A. P. Jain: We are now selling at the controlled prices, to anybody and everybody who wants to buy from us, with the result that the factories cannot sell at a higher price because we bring down the prices by our own sales.

Shri Ranga: I am extremely glad indeed for this enlightenment, and I am sure the House also would be grateful because it is a very useful step that Government have taken. But then, what would be its efficacy? That is what I would like my hon. friend to examine.

Mr. Deputy-Speaker: Not just now. He will answer in the end. This kind

of *viva voce* discussion should not be there.

Shri Ranga: This is the parliamentary way of expressing my view It is for him to give the answer, then and there. Otherwise, he can reserve it to himself I have no objection.

Mr. Deputy-Speaker: There should be something for me also in order to regulate the debate.

Shri Ranga: It is for him to ask me whether I give way or not. I have been giving way, whenever, I found that he was anxious to enlighten the House with any additional fact, and I am glad that he has given this particular fact, which certainly strengthens the case of Government And I am glad that they have taken that particular step But I would like him also to examine whether really they would be or they are in a position effectively to control or influence the retail price through the step that they have themselves taken, and whether they have enough stocks in their own possession to be able to do so Beyond that, I have nothing more to say on that point

In conclusion, I would like to say that if only my hon friend had favoured this House with the amount of information that he has given today and very much more that we would like to have, as an explanatory memorandum, it would have helped the House very much, and I am sure it would certainly have helped me to form my own view of this particular Bill as well as this particular resolution.

Shri Panigrahi: While I share with my hon. friend the Food Minister his anxiety to take measures for promoting the export of sugar with a view to earn foreign exchange, I could not share with him the assurances that he has given to justify the promulgation of this Ordinance. I think if he reviews his own arguments, he will find that they offer a poor justification for the promulgation of such an Ordinance for taking measures to promote export of sugar.

Here is an industry which has virtually doubled its production during the last five or six years There is plenty of sugar in the market. And yet, sugar is not selling cheap in the market, and the price of sugar goes on increasing. This appears quite paradoxical, but such a rise in price of sugar did occur because of the lack of a clear-cut policy on the part of the Food Ministry, so far as sugar was concerned

While I was going through the Sugar Export Promotion Bill, I had the opportunity of reading the speech or rather the substitute motion that Shri A P Jain, when he was not a Minister, moved in the year 1949. Shri Jairamdas Daulatram was then the Minister of Food The substitute motion which Shri A P. Jain then moved read as follows:

> "This House looks with grave concern at the unsatisfactory development and growth of the sugar industry in India and its failure to come up to the expectation envisaged at the time of granting protection, thereby causing huge loss to the consumers".

Then, it demanded:

> "to study and report on the working of the sugar industry, in particular, with a view to see when, if ever, Indian mills will produce sugar more or less at world competitive prices.".

I do not know whether during the last nine or ten years, the situation in the sugar industry has changed, or whether our Minister of Food has changed his views.

While moving his motion, Shri A. P. Jain then told the House:

> "Sir, the consumer was fleeced of no less a sum than Rs. 6 to 8 crores, when the Government sat calling conferences, meetings, and

[Shri Panigrahi]

committees, when every housewife was worried that she could not sweeten her child's milk with a pinch of sugar. Government was fiddling with committees' boards and conferences.".

These were the remarks which he made then.

Shri Braj Raj Singh: He seems to have forgotten them now.

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): He is not prepared to hear also.

Shri Panigrahi: These were the remarks which Shri A. P. Jain made when the great sugar scandal in the year 1949 was being debated upon and discussed on the floor of the Central Legislative Assembly.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Panigrahi should be careful, for, after ten years, he may come to this side, and he might be reminded of this.

Shri Nausher Bharucha: There is no fear of that.

Shri Panigrahi: I do not want to quote what Dr. P. S. Deshmukh said on that occasion. Unfortunately, both of them, i.e. Shri A. P. Jain and Dr. P. S. Deshmukh, are now on the Treasury Benches. I need not quote what Dr. P. S. Deshmukh said, and what he said was in even stronger terms. He wanted that any mill-owner who had made a profit of Rs. 5000 should be not only punished, but all his property should be confiscated. He had gone to the extent of demanding this.

Mr. Deputy-Speaker: Does the hon. Member want the same thing or something stronger?

Shri Panigrahi: Something stronger.

Perhaps there is something in the saying that history repeats itself. After all these 9 years, the same crisis is facing us in the sugar industry. But I would like to say that there is really no crisis in the sugar industry which necessitated the promulgation of such an Ordinance. If there is any rise in price today, it is because of the hasty step that Government took in promulgating such an Ordinance. As a result, the traders and speculators who were active got the opportunity and scope to increase the price.

My hon. friend who moved the Resolution, referred to the index of production. In fact, the index of production has gone up to a great extent. In 1953, we produced 10.01 lakh tons of sugar; in 1956-57, we produced 20.26 lakh tons. Such a huge increase in production was really a marvellous achievement on the part of the sugar industry. The Development Council for the sugar industry has also placed the production target for the current season, that is, the 1958 season, at 21.5 lakh tons. It has been calculated that the domestic consumption would at best be 19 lakh tons in the current period. The production was 19,67,000 tons upto 30th June and carry over from 1957-58 season was 4,28,610 tons; the aggregate supply with the mills comes to 23,95,610 tons. So when the sugar stocks as on 30th June with the mills were to the tune of 23,95,610 tons, what was the necessity for promulgating the Ordinance for exporting sugar? There was an exportable surplus The hon. Minister said that even when there was no Ordinance, even when no subsidy was given for exporting sugar, last year, in the season 1957, the Sugar Millowners' Association had exported 1.53 lakh tons of sugar. So the exportable surplus was there and there was no necessity for promulgating the Ordinance for achieving that result.

I was surprised to look at the quantity of sugar which has been despatched from the mills also. If we look into that, we will find that there was no necessity for creating any panic in the market by taking recourse to such a kind of Ordinance. The total despatches of sugar from the factories by 31st March 1958 were 8,08,000 tons. They came to 11,74,000 tons by 31st May. The total despatches were 13,50,000 by 30th June. Thus the

stocks with factories stood on 30th June at 10,45,600 tons. So in the market, there is plenty of sugar. Had there been no Ordinance, in the regular course of supply and demand, there was every possibility of the consumer in India getting sugar at a price less than one which is prevailing today as a result of the promulgation of the Ordinance.

There may be some reason for the Ordinance. The consumption of sugar was increasing and with a view to decrease the consumption of sugar, this Ordinance was promulgated. But if we look at the consumption figures, in 1951-52, the country was consuming 11.7 lakh tons. The consumption nearly doubled in 1955-56 when it rose to 19.43 lakh tons. The planners have calculated that at the end of the Second Plan period, our demand for sugar might increase up to 23 lakh tons. But even today, when the Ordinance was promulgated, we have stocks near about 2 million tons. So still we have plenty of stocks with us There was no necessity for us to go into the market and create such a scare which has resulted in speculators and hoarders keeping to their stocks and creating an artificial scarcity by increasing the price.

I may just refer to the exportable surplus. It has been calculated that this will come to 3 lakh tons. But the figure the Government have decided upon is 50,000 tons. So out of an exportable surplus of 3 lakh tons—a figure which has been calculated by the experts of Government themselves —only 50,000 tons were set apart for export. It was not such a huge quantity. It was only 2.5 per cent of the estimated production. The quantity which we have fixed for export is not such a huge one as to call for such an emergency measure.

I would like to submit that the upward trend in sugar price, though surprising, is because of the policy that was pursued by Government. Government pursued this policy not of its own, but the sugar millowners have actuated and rather influenced Government to take to such a policy so that they can pocket some more profit.

After the promulgation of this Ordinance, the price of sugar in various parts of the country has increased by 2 to 7 per cent. So far as Orissa is concerned, it has gone up Rs. 1-2 to Rs. 1-4 per seer. It comes to about Rs. 45 per maund. So if the ex-factory price has been fixed at Rs. 35 or Rs. 36, the consumer is paying Rs. 5 to Rs. 6 per maund more. It is because of this upward trend that the Reserve Bank of India took recourse to credit squeeze. The hon. Minister has referred to that. The directive of the Bank says that "the price of sugar has shown a rising trend during the past few months". It is not that only in the month of July the consumer has been paying a greater price for sugar, but as the directive says, "The price of sugar has shown a rising trend during the *past few months* despite the fairly comfortable supply position. It is because of the tendency of the trade to withhold stocks". Though it has taken recourse to the credit squeeze, so far as retailers are concerned, the Reserve Bank has not been able to control the retail price. The hon. Minister has admitted that though Government are in a position to fix the ex-factory price of sugar, they are not in a position to control the retail price and they are not going to resort to any measure for this purpose for the present But the sugar millowners have their own agencies and they know how to take profits whenever they want to put the Government in any critical situation.

I would like to submit that the Government have been 'waylaid' by the sugar millowners as Lakshman was in the good old days of the epic *Ramayana* by the golden deer which came across his path. With a view to earn foreign exchange, we are going to catch at anything that comes to us. The amount of foreign exchange that

[Shri Panigrahi]

we are going to earn is only Rs. 2.25 crores and we are going to suffer a loss of more than Rs. 3.5 crores. That is how the sugar millowners have put the Government in a position from which the government cannot retract. It is because in previous years they exported sugar at their own risk. Once they created this market they came upon the neck of the Government and said: You see the achievement of the Sugar Mills Association. We have created a market and if you do not come to our help we cannot export sugar and Indian sugar will lose its world market In this way, Government has been rather beguiled to take recourse to such a step.

Though I have full sympathy with the measures for exporting sugar, still I cannot appreciate the way the Ordinance was promulgated I feel Government has taken a hasty step which was not necessary and which has gone to the detriment of consumers of sugar in our country.

Shri A. C. Guha: Mr Deputy-Speaker, Sir, I think there is hardly any difference of opinion about the purpose of this Bill. I for myself do not object even to the Ordinance being promulgated, particularly, when I see that the Government took certain steps almost immediately after the Ordinance for the export of sugar. There is hardly any ground to take exception to the issue of the Ordinance

But there is something to be said about the sugar industry and the manner in which Government is handling this industry. Today the hon. Minister has given a good conduct certificate to the industry. I do not like to embarrass him by quoting what he said in 1949 while he was sitting on this side along with me. But, I hope he would recollect that he demanded an enquiry and the enquiry was conceded by the Minister then in charge, Shri Jairamdas Daulatram. I hope he must have refreshed his memory, before coming to this House on this occasion, by going through the relevant portions of the report of the Enquiry Committee. Practically, on all the charges that one-man committee found the industry to be guilty.

They charged extra premium over the price; they sent out sugar violating the freezing order of the Government; they smuggled out sugar to Pakistan; and, in the ultimate, they informed that there was a shortage of sugar, and so no export of sugar could be allowed.

Sir, I do not like to read out the relevant passages The time you would allow me won't permit that I think the findings of that enquiry committee would have, at least, made the hon Minister think seriously before giving a good conduct certificate to the sugar industry as such

Sugar production has gone up It has practically gone up by 100 per cent That is credit for the industry But, they did it for their own interests, for their own profit And, I do not think, for that reason the nation or the consumers have very much to be grateful to them That is not much point for them to get any certificate from the nation Any other capitalists —even foreign capitalists—would have done that if the proposal would give a dividend for the amount invested.

The hon. Minister has just now quoted that they have been getting only Rs 2|40 for Rs. 100|- sales. But that does not give any accurate picture of the industry. The profit that the industry has been earning on the invested capital would give the correct picture. I think, one gentleman on that side quoted some industrialist saying that the industries are earning 8 per cent dividend.

Shri A. P. Jain: I am in a position to give the figures if the hon. Member wants. The gross profit allowed is 10 per cent and, after deduction of income-tax it comes to 4.8 per cent.

Shri Tangamani (Madurai): Why this special plea?

Shri A. C. Guha: Anyhow that is the income they make on their audited accounts of their companies. But, I hope the hon. Minister knows that they have many other devices to earn income. They employ their own selling agents; they employ their own distributing agents and earn commission. I think it is a sort of menace practically to the entire industry of India that the whole panel of industrial set-up is more or less controlled by the manufacturers.

Similar is the case in the jute industry. The millowners or their own nominees are the procurers of raw jute; they are the balers of jute and after the jute goods are manufactured, they or their nominees become the shippers or exporters also So, that is the position and whether 4 8 or 4.5 per cent is allowed is not of much consequence But the main point is the control they have over the entire industry and the various ways they have earning profits

The enquiry committee of 1949 found out that they sent out sugar in contravention of the freezing order of the Government; the committee found out that they charged higher prices than was allowed; all these were to reap extra profits.

In the present case also Government have admitted that immediately after the promulgation of the Ordinance the sugar price went up by 2 to 7 per cent Who reaped the benefit? I think they might not have shown this increased rate in their account books of the factory. The enquiry committee of 1949 also pointed out that their account books were false and did not give the correct picture of the transactions that those companies were having. So, this 2 to 7 per cent higher price has also gone to the pockets of the manufacturers or some of their nominees. And the consumers have to pay this higher price.

The hon. Minister himself has admitted that, as on the previous occasion, on this occasion also some of the manufacturers have not played the game—I think this is the language he used and that some did not stick to the promise of not raising the price. Even after this, I cannot understand how he can rely on this Sugar Mills Association to be the export agency.

The Sugar Mills Association is just a metamorphosed form of the Sugar Syndicate of India. (*Interruptions*).

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

Shri A. C. Guha: I think the story of the Sugar Syndicate of India is known at least to the older Members of this House. (*Interruption*).

Shri Braj Raj Singh: Very well to Shri Jain

Shri A. C. Guha: Very well to Shri Jain So, I do not know why he has selected this Sugar Mills Association as the export agency I shall come to that later on

Shri Mahanty (Dhenkanal): Because they are experienced in exploiting.

Shri A. C. Guha: The hon Minister has admitted—and we also find from some report—that last year the industry exported 1.53 lakh tons of sugar without any government help or subsidy. Why just in one year there is an occasion for this great gap between the world market and the Indian cost of production?

I find from some report—the figure is given by the Minister in sterling—in Indian currency Rs. 420/- is the cost of foreign sugar and Indian sugar costs Rs. 750 per ton. That means it costs 80 per cent more. I do not know whether the Minister has got the entire cost structure of the sugar industry examined by the Tariff Board recently. It should be done annually. Unless that is done, you cannot be sure as to the actual cost of production. I wish

[Shri A. C. Guha]

the Minister may get this thing examined. It will help the Members to understand why one year ago, the industry was able to export 1.53 lakh tons of sugar without any Government subsidy and why this year for exporting only 50,000 tons of sugar, so much Government subsidy is necessary and at the cost of the consumers.

Shri Satyendra Narayan Sinha (Aurangabad—Bihar): That is because of the world prices.

Shri A. C. Guha: Why this big difference in the Indian price?

Shri Satyendra Narayan Sinha: The Minister explained.

Shri A. C. Guha: He has not explained why our cost of production should be so high. That is the point which should be examined by the Tariff Board.... *(Interruption)*.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Time is flying.

Shri A. C. Guha: Sir, time is eternal but life is short.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): He is a philosopher now.

Shri A. C. Guha: One has to be occasionally.

Coming to the Bill, I do not know how he has accepted a new definition of the term 'owner'. I think it would leave some lacuna. He could have accepted the definition given in the Industries (Development and Regulation) Act or the Mines Act. There is also the definition of 'occupier' in the Factories Act. He may have accepted any of these definitions instead of this definition. I am afraid that this definition would not cover some of the categories of persons in charge of these factories.

Shri A. P. Jain: Will he kindly point that out?

Shri A. C. Guha: For instance, the managing director may not be covered. Anyhow, that is a point to be decided in the law court. I know that he must have been told that it would cover that also. But I do not know when a definition was accepted by this House and the Government on a previous occasion and put in two or three enactments, why a new and combrous definition has been put here. That definition was much simpler.

Then I refer to various provisions in clause 7. I for one have very serious objection to the provision that if a factory fails to deliver the required quantity of sugar, that factory will only have to pay an additional penal excise duty as in clause 7(1). If it is necessary for the factory to surrender certain quantity of sugar for the purpose of export it has to deliver that quantity. There should not have been any penal excise, thus allowing the company to get over the directives of the Government. A similar provision has also been put for the textiles industry. I think it is morally wrong and it encourages violations of Government order also. I cannot understand how a company can evade paying excise duty on any quota to be delivered to it and why the duty is to be realised later on as in clause 7(3). Under the present excise rules, no quota of sugar or other articles which are subject to excise duties, can be released from the godown or factory without paying the excise duty.

Coming again to the export agency, I am not satisfied with the explanation given for not taking the State Trading Corporation as an export agency. It is a Government organisation which has been set up particularly for the promotion of exports and also for the import of certain articles. I also do not like the provision in clause 8(2) which says that notwithstanding anything to the contrary contained in the memorandum or articles of association of the company as the case may be, the company may perform all such

functions. I would draw the attention of Pandit Thakur Das Bhargava to this clause. Does it not mean that by this clause we are amending the memorandum and articles of association of all the sugar mill companies They may not be exporters according to their articles of association. But by this Bill, we are amending the articles of association and allowing them to export sugar In the export licence policy of the Government, I think there is something like an established exporter Usually, export licences are not given to those who are not established exporters. I do not know why these factories should have been given this facility. It should have been done through the STC. With these words, I support the purpose of this Bill and I think that there should be some modification in certain clauses

श्री राजश्री वर्मा (देवरिया) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने चीनी के रोजगार को बढ़ा कर और विदेशों में जो उसका मार्केट ढूंढ निकाला है वह सराहनीय है। मुझे खुशी है कि सरकार ने फारेन एक्सचेंज के लिए एक रास्ता निकाला जिसकी कि मुल्क को आवश्यकता है किन्तु जिस ढंग से और जिस तरीके से इस रास्ते पर सरकार पहुंची है उसकी कोई सराहना नहीं कर सकता ।

अभी मेरे साथी ब्रजराज सिंह ने आर्डिनेन्स के मुताल्लिक चर्चा की । मैं उन के साथ सहमत हूं कि आर्डिनेन्स की कोई आवश्यकता नहीं थी । यह ठीक है कि आपने चीनी का एक नया मार्केट विदेश में खोज निकाला है और दूसरे मुआमले के लोगों को चीनी जैसी मीठी चीज जो आप खिला रहे हैं और एक मधुर सम्बन्ध जोड़ना चाहते हैं, वह सराहनीय है लेकिन उसकी सराहना करते हुए भी मैं आपका ध्यान चीनी व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं

उपाध्यक्ष महोदय . आप इस मीठेपन में कड़वापन क्यों डालना चाहते हैं ?

श्री राम जी वर्मा उपाध्यक्ष महोदय, यह शुगर का व्यवसाय बड़ा कड़वा रहा है । इस मुल्क में बार बार प्रोटेक्शन देने के बाद भी यह रोजगार विदेशी रोजगार के मुकाबले नहीं आ सका । अगर आप सन् १९५६-५७ की शुगर की प्रोडक्शन फीगर्स को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि सन् ५६-५७ में देश में कुल ३० लाख २६ हजार टन चीनी पैदा की गई किन्तु सन् १९५७-५८ में मुल्क में केवल १६ लाख ६७ हजार टन चीनी पैदा हुई है । अगर यह आंकड़े सही हों तो सन् ५७-५८ में सन् ५६-५७ के मुकाबले ५६ हजार टन चीनी कम पैदा हुई है और आप चीनी के लिए बाहर मार्केट खोज रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि करीब १ लाख टन चीनी की कमी आपके मुल्क में कन्ज्यूमर्स को खपत के लिए होगी ? आखिर आपने इसके लिए क्या उपाय सोचा है और रास्ता निकाला है ? यह तो जाहिर बात है कि जब मुल्क में चीनी की कमी होगी तो चीनी का भाव बढ़ेगा, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी और लोग परेशान होंगे इसका मंत्री महोदय को मनोपजनक उत्तर देना चाहिए।

दूसरी बात जिसकी कि ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि बहुत प्रयास के बाद भी उस मधुर सम्बन्ध में सिर्फ आपने १७ हजार टन चीनी का सौदा किया है लेकिन यह पता नहीं है कि भेजी कितनी है

14 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय उन्होंने कह दिया है कि आधी भेज चुके हैं।

श्री रामजी वर्मा : मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपने जो यह तय किया है कि कम चीनी पैदा होने पर भी आप बाहर चीनी भेजना चाहते हैं और अपने मुल्क वालों को कम चीनी खिला कर भी फारेन एक्सचेंज कमाना चाहते हैं तो यह मुल्क उस सैक्रिफाइस के लिए भी तैयार है लेकिन जैसे कि कुछ अन्य वक्ताओं और प्रोफ़ेसर रंगा ने यह आशंका प्रकट की है कि क्या हम इस मधुर सम्बन्ध को और व्यवसाय को कायम भी रख सकेंगे मुझे भी शक है कि आप उनको कायम नहीं रख सकेंगे और वह इसलिए की आपने इस देश में चीनी व्यवसाय में जो इसको पैदा करने वाले ग्रोअर्स हैं उनकी आपने अब तक उपेक्षा की है और अब भी कर रहे हैं। आपने गवर्नमेंट रेवेन्यूज में तो करोड़ो की बडहोत्री की है।

मेरा ख्याल है कि सन् १९५१-५२ में आपका शुगर से रेवेन्यू ८ करोड़ था जब कि आज ४२ करोड़ इस व्यवसाय से आप ले रहे हैं। इस व्यवसाय में सरकार को भी नफा हुआ है, मिलओनर्स को भी नफा हुआ है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो इस व्यवसाय की बुनियाद है, किसान, क्या उसको भी नफा हुआ है ? सन् १९५१-५२ में आप ग्रोअर्स को गन्ने की कीमत १ रुपया १२ आने मन देते थे। आज वह घटा कर १ रुपया ५ आना और १ रुपया ७ आना कर दी गयी है। सरकार की तरफ से जो टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट शाया हुई है उसमें बताया गया है कि जब चीनी का भाव २७ रुपया मन हो तो ग्रोअर्स को एक रुपया १२ आना मन गन्ने का दाम मिलना चाहिए। आज चीनी का भाव क्या है और आप ग्रोअर्स को कितना दे रहे हैं। अगर आप गरीब का मुनाफा काटना चाहते हैं तो उतना ही काटिये कि वह जिन्दा रहे क्योंकि अगर वह जिन्दा रहेगा तभी आपकी यह मोटी आमदनी भी चल सकती है।

मैं आप से कहूं कि एक्साइज़ ड्यूटी के नाम पर केन्द्रीय सरकार और सैस के नाम पर स्टेट गवर्नमेंट हर साल करोड़ों रुपया लेती है। यह कहा जाता है कि गन्ने को इम्प्रूव किया जायगा। श्रीमन्, अभी हिन्दुस्तान की भूमि में इतनी ताकत है कि उपज बढ़ायी जा सकती है। आपने गत वर्ष ग्रोअर्स को इनाम दिया था उस से मालूम होता है कि भारतवर्ष की जमीन में अभी उपज बढ़ायी जा सकती है। किन्तु मुझे उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में मालूम है कि वहां पर दस पन्द्रह बरस पहले जितनी पैदावार होती थी उतनी आज नहीं होती बावजूद इसके कि डवलपमेंट कमटिया नियुक्त की गयी है और डवलपमेंट विभाग भी कायम हो गया है। तो एक तरफ तो आप इस व्यापार को विदेशों में ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ आपकी बुनियादी कमजोरियां ये हैं, तो आप ऐसी हालत में इस रोजगार को कहां तक चला सकेंगे। मुझे तो इस में सन्देह है। मुझे खुशी होगी अगर आप इसको जिन्दा रख सकें। और इसके द्वारा मुल्क के लिए फारेन एक्सचेंज पैदा कर सकें। लेकिन इस से लेबरर और ग्रोअर को भी फायदा होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट की जो पालिसी है वह ग्रोअर्स के लिए बहुत ही, दोषपूर्ण है। मैं इसलिए ही आपका ध्यान इस तरफ अधिक आकर्षित करना चाहता हूं कि आपको भी अब यह सूझ गया है कि यही एक चीज है जिसको आप विदेशों में ले जाकर बेच सकते हैं और उस से कुछ विदेशी विनिमय पैदा कर सकते हैं। मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप इस उद्योग को बुनियादी तरह से देखें।

आप देखें कि आपने कितने ट्यूबवैल बनाये हैं, कितनी खाद की और दूसरे साधनों की सुविधा दी है ताकि यह चीज बढ़ सके। अगर समय होता तो मैं एक एक स्टेट के फिगर आपके सामने रखता और बतला देता कि इस में स्टेट सरकारों और केन्द्रीय सरकार की कितनी उपेक्षा की दृष्टि रही है। मेरा सुझाव है कि अगर आप इस उद्योग के द्वारा फारिन एक्सचेंज पैदा करना चाहते हैं, तो आप इसकी उपेक्षा न करें चाहे स्टेट सरकारें भले ही ऐसा करें। मैं चाहता हूं कि जो आपको फारिन एक्सचेंज इस व्यवसाय से प्राप्त हो उसको आप शुगर केन के डेवलपमेंट के लिए, अच्छे औजारों के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, सिंचाई के साधनों के लिये और रिसर्च वर्क के लिए खास तौर पर खर्च करें। यहां पर अभी तक गन्ने की किस्में बहुत बढ़ी नहीं हैं। वही पुरानी किस्में चल रही हैं। हां कहीं कहीं पर कुछ काम हुआ है, लेकिन अभी ईल्ड वही है बल्कि घट रही है। कुछ वर्ष पहले यहां पर गन्ने का सूक्रोज कंटेंट १० से ११ प्रति शत तक होता था जो कि अब ९ और कुछ प्रतिशत रह गया है। तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में रिसर्च वर्क करें और किसानों को यह जानकारी पहुंचायें।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाहर भेजने का काम इंडियन मिल्स एसोसिएशन को दिया गया है। प्रोफेसर रंगा साहब ने कहा कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को यह काम क्यों नहीं दिया गया। इसका माकूल जवाब मिलना चाहिए। दूसरी तरफ आप जो काम डायरेक्टर आफ शुगर एंड वनस्पति को सौंपते हैं उस से तो अच्छा होता कि आप एक्सपोर्ट प्रोमोशन्स कौंसिल बनाते जिस में सरकारी और गैर-सरकारी लोग होते और वे लोग आपको सलाह देते और उस पर आप चलते।

हमारे कई भाइयों ने आपसे पूछा कि बीच में आपने आर्डिनेन्स बना कर जो चीनी बाहर भेजने का प्रबन्ध किया है उसका क्या कारण था। इसका आपके पास क्या माकूल जवाब है। आपको यह चीज लोगों को बतलानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोगों में यह शुबहा हो सकता है कि आज आप मिल वालों के साथ वही सम्बन्ध निभा रहे हैं जो चुनाव के समय उन्होंने आपके साथ निभाया था। इसका जवाब आप को देना होगा।

इस इंडस्ट्रीज की भलाई के लिये, मुल्क की भलाई के लिए और यह जो नया व्यापार हम विदेशों से करने जा रहे हैं उसकी प्रास्परिटी के लिए आप अपने दिल और दिमाग को साफ रखें और अपनी नीयत भी साफ रखें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (अम्बाला) उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे सामने जो बिल उपस्थित है उसका मैं स्वागत करती हूं और जो इसके विरोध में प्रस्ताव लाया गया है उसका मैं विरोध करना चाहती हूं।

अभी कुछ माननीय सदस्यों ने बतलाया कि जब सदन का सेशन नहीं हो रहा था ऐसे वक्त आर्डिनेन्स क्यों लाया गया। इसका मंत्री जी ने जो जवाब दिया था मैं उस की ताईद करती हूं। जो कुछ किया गया जब उस पर हम लोगों को और माननीय सदस्यों को ऐतराज नहीं है तो किस वक्त किया गया इस बात पर ऐतराज करने में कोई बहुत ताकत नहीं मालूम होती।

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

हमें यह भी बतलाया गया कि इस बरसे में उन्होंने कुछ मशीनरी भी लगाली और कुछ आर्डर्स भी दे दिये और कुछ इन्तिजाम कर लिया । इसका भी हम लोगों को खयाल रखना चाहिए । मैं समझती हूं कि छोटी सी बात पर इधर से नाक पकड़ा या उधर से पकड़ा जावे इस में ज्यादा मीन-मेख निकालकर हम लोगों को इसका अपोजिशन नहीं करना चाहिये ।

जहां तक चीनी की कीमतों का सवाल है, मैं एक चीज खास कहना चाहती हूं । मिल वालों के हाथ कम किये जाय बहुत अच्छा है । इसका भी मैं स्वागत करती हूं । अगर हो सके तो गन्ना उगाने वालों को ज्यादा पैसा मिले, यह भी बहुत अच्छा है । पर आज जो सरकार ने स्टाक लेकर चीनी की कीमतें मुकर्रर कर दी हैं उस पर लोगों को चीनी मिल सकती है । यहां पर कहा गया है कि जब एक्सपोर्ट की बात की गयी तो मिल के मालिकों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वह चीनी के दाम महंगे नहीं करेंगे । मैं भी उन लोगों में से हूं जो कि इन तमाम बातों में भरोसा कम करते हैं । और मुझे इस में कोई शुबहा नहीं है कि अगर खुली छूट मिल जाये तो चीनी मिल वाले . हों चाहे कोई और व्यापारी हों वे लोगों की मुसीबत से ज्यादा से ज्यादा फायदा करने की कोशिश करेंगे और उनके सामने कोई यह सवाल नहीं आता कि कौन मुसीबत में पड़ा है, किसको कम मिलता है किसको ज्यादा मिलता है ।

पर यह जो फारिन एक्सचेंज लेने का तरीका अख्तियार किया गया है मैं उसका स्वागत करती हूं । अभी हमारे सम्मान्य प्रो० रंगा साहब ने कहा कि इसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारी बहुत सी जमीन जो कि गेहूं के लिये और दूसरी खाने की चीजों के लिये इस्तैमाल होनी चाहिए उस पर गन्ना उगाया जा रहा है और इसलिये गन्ने से गल्ला कम होता है । इसी तरह से हमारे सामने यह भी सवाल आता है कि हम फ़ारेन एक्सचेंज कैसे हासिल करें और अपने देश में कितनी चीनी या कितनी गेहूं इस्तेमाल करें । इस विषय में कोई प्रोपोर्शन रखने और उनका आपस में ताल्लुक समझने की बात सामने आती है । अगर हम चीनी दे कर, या कम खाकर—यहां कम खाने की बात नहीं है—फ़ारेन एक्सचेंज बढ़ा सकते हैं, तो उस का स्वागत करना चाहिए और मैं भी उसका स्वागत करती हूं । जहां तक कीमतें बढ़ने की बात है, मुझे एक बात से बड़ा रंज हुआ है, जिस को कि मैं आज कहना चाहती हूं । जिस वक्त हमारे यहां फूड की डीबेट हो रही थी, उस वक्त भी मैंने इस सदन के माननीय सदस्यों की बातें सुनी थीं और आज भी सुनी हैं । मुझे खुशी हुई कि चीनी बनाने वाले जो फ़ायदा उठा रहे हैं, उस पर यहां तुलना-चीनी की गई, उस की आलोचना की गई और कहा गया कि वे लोग नाजायज फायदा उठाते हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए । लेकिन दोनों डीबेट्स में मैं ने देखा कि जो दूसरे फ़ायदा . उठाने वाले हैं, उन की तरफ़ कोई इशारा नहीं करता है । अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि चीनी के मिल मालिक चुनावों के वक्त जो रिश्ता कायम करते हैं, मंत्री जी उस रिश्ते को कायम रखे हुए हैं । मैं यह कहना चाहती हूं कि मंत्री जी बड़े आदमी हैं । हो सकता है कि चीनी के मिल-मालिक उन से रिश्ता कायम रखते हों, लेकिन हम लोग, जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं,

चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, भी अपने रिश्ते निभाते हैं—जो मिडलमैन हैं, जो व्यापारी हैं, वे लोग हम से जो रिश्ता कायम करते हैं, हम वह रिश्ता निभाते हैं ।

आज यह कहा जाता है कि सरकार रीटेल प्राइस को कंट्रोल क्यों नहीं करती है । लेकिन क्या हम लोग, जो कि लाखों की नुमायदगी करते हैं, इस बारे में कोई कदम उठाते हैं, कोई मदद करते हैं या नहीं । एक तरफ हम कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं जम्हूरियत में विश्वास करते हैं । जितनी पार्टीज यहां आती हैं वे जम्हूरियत में यकीन करती हैं । हम प्लानिंग करते हैं और उस में विश्वास रखते हैं, लेकिन जब तक उस में जनता का को-आपरेशन नहीं होता है, जनता के नुमायदों का को-आपरेशन नहीं होता है तब तक प्लानिंग सफल नहीं हो सकता है, फिर चाहे कितने ही कानून हम यहां बनाते रहें ।

एक साहब से मेरी बातचीत हुई । वह यहां के सदस्य नहीं हैं । वह यह प्रोग्राम बना रहे हैं कि यू० पी० में गवर्नमेंट के गोदाम लुटवाये जायें । मैं ने उन से पूछा कि क्या यू० पी० में फेयर-प्राइस शाप्स हैं । उन्होंने कहा कि "हैं" । मैं ने उन से पूछा कि "क्या कभी आपने किसी दुकानदार के सामने खड़े हो कर यह देखने की कोशिश की है कि वह दुकानदार कैसे बिक्री करता है और अगर कोई गलत तरीके से बिक्री करता है, तो क्या आपने उस का विरोध किया है, उसके हाथ मिलाने से इन्कार किया है, क्या कभी उसकी दावत में शरीक होने से इन्कार किया है । वही आदमी हजारों बोरी गेहूं या चीनी वगैरह रख कर भी नहीं बेचता है, गलत बेचता है या महंगा बेचता है, तो क्या आप ने कभी जनता से कहा कि यह व्यक्ति गलत काम करता है, हमारी प्लानिंग में रुकावट डालता है, हमारी खाद्य समस्या को बढ़ाता है—कम नहीं करता है ? क्या आपने कभी यह किया ? या सिर्फ सरकार का गोदाम लुटवा कर ही आप कामयाब हो जायेंगे ?" मुझे खुशी हुई कि उन्होंने खुले दिल से जवाब दिया—यह हमारी आपस की बात थी और इसलिए उन्होंने सफाई से कहा—कि हमारे देश में एक ही बात है, जिस पर तमाम सियासी जमायतें मुत्तफिक हैं और वह यह कि कोई काम न करो और सिर्फ नुक्ता-चीनी और आलोचना करो । यह बात उन्होंने कही । वह गलत होगी । मैं सिर्फ उनकी बात बतला रही हूं । उन्होंने कहा कि किस को फुरसत है कि वह यह देखता फिरे कि कौन किस भाव से बेचता है । उन्होंने कहा कि हम को तो लैक्चर देने की फुरसत है और हम ने लैक्चर दे दिया है । वह यहां दिल्ली में खाद्य मंत्री से बात-चीत करने के लिए आए हुए हैं ।

यहां पर दिल्ली की कीमतों का भी जिक्र हुआ । एक दिन और एक सदस्य साहब ने जिक्र किया और नाम भी लिया था कि मैं चीनी बेचती हूं । मैं बेचती नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसा इत्तजाम है कि कुछ बरसों से

उपाध्यक्ष महोदय बहुत मुश्किल हो जायगी अगर जो भी जिक्र वह करे वह आप बयान कर दें ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी मैं जनता के सहयोग की बात कर रही हूं । हमने इस बात की कोशिश की कि सरकार गेहूं का

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

चीनी की भी कीमत मुकर्रर करे या जिस पर लोगों को खरीदने में आसानी हो, उस कीमत को मुकर्रर करें। इस में कुछ दुकानदारों ने अपना सहयोग दिया है। शायद हमारे माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि आज भी कुछ दुकानें ऐसी है, जो साढ़े पन्द्रह आने सेर के भाव पर चीनी बेचती हैं, जो भी चाहे ले सकता है। ऐसी दुकान पुरानी दिल्ली में खास तौर पर हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगी कि वे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली की सिर्फ़ चीनी की कीमतों का ही मुकाबला न करें। वे सब्जी का भी मुकाबला करें। जो लोग नई दिल्ली में सब्जी खरीदते है, वे हर पाव पर चार छ आने ज्यादा कीमत देते हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि इन कीमतों का फूड मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी पालिसी से कोई ताल्लुक नहीं है—उसका ट्रांसपोर्ट और दूसरी बातों से ताल्लुक रहता है। अगर यहां पर कुछ लोग मुनासिब कीमत पर चीजों को बेच सकते है, तो कोई वजह नहीं कि दूसरे शहरों में भी जनता के सहयोग से ऐसा न हो। मैं खाद्य मंत्री महोदय से कहूंगी कि वह कोई ऐसा सिलसिला बनायें—या तो इस बिल में कुछ प्रोवाइड करें या लोगों से अपील करें—कि हर एक चीज की मुनासिब कीमत मुकर्रर की जा सके। यह सरकार निगरानी करे या खुद इसका इन्तजाम करे।

माननीय सदस्यों ने कहा कि जो शुगर मिल्ज के एजेन्ट हैं, वे इसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहां भी ऐसा हुआ। हम ने कहा कि जो भी चाहे, हमारे गोदाम से चीनी ले जाये, लेकिन हम ने देखा कि आठ नौ दिन तक कोई चीनी नहीं लेने आया। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहती हूं कि सरकार और पब्लिक के सहयोग से हम इस मुश्किल को हल कर सकते हैं। खाद्य मंत्री, लोगों, सियासी जमायतों, लोगों के नुमायंदों का सहयोग लेकर दूसरे शहरों में मुनासिब इन्तजाम कर सकते हैं।

आज हमारी वैल्यूज चेंज हो गई हैं। आज जो ज्यादा महंगा बेचता है, उस की समाज में कद्र है, जो कोई ग़लत काम करता है, समाज में उसकी तारीफ़ की जाती है, जो कोई बिना टिकट ट्रैवल करता है, वह शेखी बघारता है कि मैंने बड़ा बहादुरी का काम किया है। हम इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। खाद्य मंत्री को इसका इंतजाम करना चाहिए। जहां तक कीमतों का ताल्लुक है, मैं इस बात के विरोध में हूं कि कानून के जरिये रीटेलर की कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाय। कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि जिस तरह आसानी से वे बेच सकते हैं, उन को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाय और जो लोग सस्ता बेचते हैं, उन को और ज्यादा सहूलियत दी जाय। अगर मुनासिब कीमतें रखी जा सकती हैं, तो इसी तरीके से रह सकती हैं—और कोई तरीका नहीं है।

इतना कह कर मैं इस बिल का स्वागत करती हूं और मुझे कोई शुबहा नहीं कि अगर हम ठीक तरीके से काम करें और जो दिक्कतें सामने आयें, खाद्य मंत्री महोदय उन पर ध्यान देते रहें, तो हम बाहर से करेन्सी भी ला सकेंगे और अपने यहां भी चीजों की कीमतों को नीचे रख सकेंगे।

Shri Naushir Bharucha: Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to oppose the Bill not merely because it has been introduced after an ordinance has been promulgated, but because the very subject-matter of the Bill is such that a little analysis would show that this step should never have been taken by the Government. The need for foreign exchange is there, but that seems to be merely an excuse in this particular case for promulgating that ordinance. When the hon. Speaker was pleased to call upon the hon. Minister to justify the promulgation of the ordinance, he said the justification was that 9,900 tons of sugar earning Rs. 50 lakhs of foreign exchange was exported. Rs. 50 lakhs of foreign exchange is just enough for this country to last for six hours! It is not even worth mentioning; for that to have promulgated the ordinance is an abuse of the ordinance-making power.

We are depleting our foreign exchange resources at the rate of something like Rs. 3 crores to Rs. 4 crores every week. That is only the loss over and above what the exports pay for. How long is this Rs. 50 lakhs of foreign exchange going to help us? Earning foreign exchange which will keep the country going for just six hours and this is the justification for rushing through with this ordinance.

Apart from that, why was sugar selected as the subject-matter for export promotion? I shall tell you why. This seems to be nothing short of a racket of sugar barons to exploit the country. What type of commodity should be selected for export purposes? Not the one where the difference between the world market and our cost of production is Rs. 10 per maund and more. Surely there must be some sense in selecting a particular type of commodity for purposes of export promotion. I do not say that that particular commodity should have a monopolistic position in the world market, but certainly it should have a predominant position in the world market. Also, the export promotion should not be at excessive loss to Government revenue or national income. The commodity to be exported should have a large exportable surplus, so that the internal domestic market is not disturbed. As I said, if the difference is so much as this, then it is futile and foolish to select a commodity for the purpose of export, because you are making sacrifices without getting any substantial return.

The difference between the world price and our cost of production is as Rs. 10 per maund, which means very nearly 30 per cent. of the cost of production. I ask, who bears that burden of subsidy, because the exports have to be subsidised? Either the consumer pays it in the form of higher prices, or the cane-grower pays in the shape of still lower minimum price or the Government pays in the shape of loss of excise duty, income-tax, corporation tax and so forth, or the factory owner pays in the shape of lesser profits. The Government has decided already that the consumer must be made to pay it. What is the justification for this? They say that we are earning foreign exchange and we shall export 50,000 tons. It is estimated that 50,000 tons will earn, depending on the price, foreign exchange worth between Rs. 2¼ crores and Rs. 2½ crores. In other words, the whole year's efforts at export, with so much burden to the consumer and loss of national income, will fetch foreign exchange which is just enough to make good the deficit in our foreign exchange resources for less than one week.

When that is the case, may I ask why this was done? Could you not have selected any other commodity which has a commanding position in export trade, such as tea? Nothing has been done for that, but instead sugar has been selected.

Let us consider the position. So far as the cane-grower is concerned, he gets at the rate of Rs. 1-5-0 for

[Shri Naushir Bharucha]

supply of cane at the out-centre and Rs. 1-7-0 for supply of cane at the mill gate. That itself is below the cost of production, because when the prices were fixed, an under-estimate was made for every item whether it is agricultural machinery, or irrigation rates or cess. When the price was fixed at Rs. 1-5-0, the Government said it would give the cane-grower one anna per maund as profit. But actually what happens is, when the mills buy cane after May, the prices slash down to as low as 12 annas, because they say that cane after the month of May does not yield so much; on that basis, this is done. Not only that. In Bombay, as my hon. friend, Shri Jadhav tells me, some of the sugar mills take a deposit from the cane-growers to the extent of Rs. 10 per ton, so that he may again go there the next season and supply cane.

Shri Bishwanath Roy (Salempur): Are there no unions of growers?

Shri Naushir Bharucha: I am talking of Bombay. Nobody cares for the consumer and the cane-grower and these things are done. The only two interests which are safeguarded are the Government's interests and the profits of the mill-owners.

Now, where are we going to export this sugar? It has been stated that the Sugar Mills Association had built up its exports at various places like China, Malaya, Burma, Ceylon, Iran, Iraq, Saudi Arabia, Sudan and East Africa. These are the markets at which these exports have been built up. The excuse on the part of the sugar barons is this: unless Government does something about it, our export market would be lost. What is the export market? 50,000 tons. For that, what are we paying? For every maund that we export, we are getting Rs. 10 less. In other words, our national income is poorer for every maund of sugar that we export. Surely, if the hon. Minister says that foreign exchange is useful for the Second Five Year Plan, are not our internal resources equally important for the Second Five Year Plan? What does it actually come to? In this particular case it means the devaluation of the rupee. For the same amount of rupees, you get less of foreign exchange; in effect it is that. And whenever there is devaluation of currency, it is the consumer who pays.

What is more, for Rs. 2½ crores of foreign exchange that we get, what is the burden that is imposed upon us? It has been stated that because of this export, the price of sugar will be increased at the rate of 50 nP per maund. So it will come to about 1 nP per pound. Every time the consumer is made a scapegoat and they say it is only 1 nP or 2 nP and so on. I ask whether the time has not come to follow a more enlightened policy.

I say that the scheme of the Bill is basically wrong for this reason that they have adopted a wrong policy and taken a wrong commodity for the export market. They keep on paying for it and make the consumer bear all the burden. The hon. Minister is not justified in doing that. Why has a wrong commodity been selected for export promotion? My charge against the Government is that they have done so because of this racket of the sugar barons to exploit the consumer in which the Government willy-nilly helps.

So far as the scheme of the Bill is concerned, I should like to have a few more facts. Apart from the constitutional objections which might be urged later on, apart from that, the first point is why this export agency has been created? Why should it be in a monopolistic position? Why should there be only one export agency? Why is export not permitted by others? The second point is: how are the profits of this export agency going to be utilised. Thirdly, we do not know what is in the Government's mind with regard to the payment of price to the factory

owner who delivers the quota to the export agency. If it is the intention of the Government to build up an export market then why should you select a commodity where there may be shortage even in the home market at a later date? Then, if there is a loss, who bears the loss? Will the export agency suffer that loss?

There is one last word and I shall conclude. Again I may say that this can be regarded as a racket of the sugar barons to exploit the consumer. It may be argued that the export agency is not going to make any profits. It will run this business, as far as possible, on "no profit; no loss" basis. Therefore there is no racket. Even the sugar factory owners will not get anything more than the price minus the expenses. I shall explain the reason. Today the potential for sugar production in India is far more than can be utilized. In fact, it is an over-capitalised industry. There are 202 sugar mills out of which in one season barely 75 per cent. work The sugar baron is interested in seeing that his extra idle capacity is utilised How can that be utilized? Start an export racket. Whether the commodity is fit for promotion as an export commodity, that does not matter. But if this additional idle capacity, if that can be utilized, that capacity will start paying him dividends. For this the consumer is made the scapegoat. I strongly protest against this Bill, which is nothing short of exploiting the consumer, who is unable to suffer any more.

श्री झुन झुनवाला : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में ही मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं शूगर इंडस्ट्री का कोई हिमायती नही हूं और हमारे भाई ब्रजराज सिंह जी ने जो बातें कही हैं और बताया कि इतना लाभ वे उठा रही हैं और उनको एक्सपोर्ट में कोई विशेष रिआयतें देने की आवश्यकता नहीं थी, यदि वे सच हैं, और मिलें अनावश्यक या गैर वाजिबी तौर पर फायदा उठा रही हैं, तो उसको रोका जाना चाहिये । लेकिन जो आंकड़े उन्होंने पेश किये है उनमें मुझे कुछ संदेह मालूम पड़ता है । लेकिन फिर भी मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उनके बारे में वे जांच करे ।

मगर मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि किसने कितना फायदा उठाया इसको लेकर यदि हम केवल इंडस्ट्री को ही देखेंगे तो हम जो वास्तविक स्थिति है उस पर नही पहुंच पायेंगे और केवल स्लोगन की बात को ही ले करके इस उद्योग को हम खत्म कर डालेंगे । इस वास्ते हमको देखना चाहिये कि जो स्थिति आज पैदा हुई है वह क्यों पैदा हुई है तथा आज जो हम शूगर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे हमको उतनी आमदनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिये और जो टैक्स इस इंडस्ट्री पर लगा हुआ है उतना दाम भी हमको एक्सपोर्ट से नहीं आता है । मैं चाहता हू कि अब जो दाम हम देते हैं उसको अलग छोड़ दें, जो मैनुफैक्चरिंग कास्ट है, उसको अलग छोड़ दें, मिलें जो नफा कमाती है उसको भी अलग छोड़ दें, लेकिन हम यह तो देखें कि किस भाव में हम बाहर चीनी भेज सकते है और किस भाव पर हम यहां पर पैदा कर सकते है । जहां तक फारेन एक्सचेंज का सम्बन्ध है, कौन नही चाहेगा कि हमें फारेन एक्सचेंज मिले और अधिक से अधिक फारेन एक्सचेंज हम पैदा करे । यह भी जरूरी है कि जब हम फारेन एक्सचेंज पैदा करने की चेष्टा करते हैं तो हमारे यहां के जो दाम है चीजों के, वे कुछ बढ़ जायेंगे और बढ़े हुये भावो पर चीजें यहां हमको बेचनी पड़ेंगी । लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि किसी के ऊपर बहुत अधिक बोझा न पड़ने पावे । यह तो साफ है कि कंज्यूमर्स को भी थोड़ा बहुत बोझा जरूर सहना पड़ेगा । लेकिन यदि जो कुछ मेरे भाई ब्रजराज सिंह जी ने कहा कि जो भी अधिक लाभ हो रहा है, वह सारे का सारा इंडस्ट्री को जा रहा है, यदि यह सच है और यदि इंडस्ट्री गैर वाजिबी

[श्री झुनझुनवाला

तौर पर फायदा उठा रही है तो मैं चाहता हूं कि उसकी इन्क्वायरी हो और उसको रोका जाये । परन्तु हमको यह भी देखना चाहिये कि और कौन दूसरे लोग है जो इससे लाभ उठाते है । मैं इसी सदन में बहुत बार कह चुका हूं और आज फिर मैं उसको दोहराता हूं कि कंज्यूमर्स का फायदा देखने वाली न यहां पर सरकार है, न ग्रोअर है और न ही शूगर इंडस्ट्री है । एक शूगर कंट्रोल बोर्ड हुआ करता था, आजकल वह कायम है या नही मैं नही जानता । उसमें इन तीनो के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे और आपस मे मिल कर के अपनी अपनी मांगें पेश किया करते थे । सरकार कहा करती थी कि हमारी एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ जानी चाहिये मैस इतना बढ जाना चाहिये ग्रोअर कहता था कि हमारे केन की प्राइस इतनी बढ जानी चाहिये, मिल वाले कहते थे कि हमको इतना प्राफिट हो जाना चाहिये । तीनो मिल कर यह फैसला कर लिया करते थे कि तुम इतना प्राफिट ले लो, तुम केन की इतनी प्राइस ले लो और सरकार इतना कर ले ले । किसको क्या लाभ होता है, हम क्या काम करते हैं, हमारी एफिशेंसी क्या है, इसको कोई देखता नही था और अगर देखता भी था तो कोई परवाह नही करता था । सरकार जो हमसे टैक्स लेती है, उसके बदले में इस इंडस्ट्री को कुछ देती है या नही यह देखना सरकार का काम नहीं रहा । सरकार को तो बस टैक्स मिलना चाहिये और जब उसको टैक्स मिल जाता है तो वह अपने घर में बैठ जाती है और यह नही देखती कि उसका क्या असर कंज्यूमर पर जा कर पड़ता है या दूसरों पर पड़ता है । जब ग्रोअर को केन का मूल्य एक रुपये से बढ़ कर एक रुपया एक आना मिल जाता है तो वह सन्तुष्ट हो जाता है और वह अपने घर में जाकर बैठ जाता है । जब मिल वालों को दो चार प्रतिशत अधिक प्राफिट मिल जाता है तो वे भी अपने घर में चुपचाप बैठ जाते है और किसी दूसरी चीज की उनको भी फिक्र नही रह जाती है । सरकार ने जब सैस वगैरह लगाये थे, उस वक्त उसने क्या कहा था ? सरकार ने कहा था कि हम केन इस तरह का पैदा करवायेंगे कि जिससे हमारे केन में सैक्रोस कंटेंट एक आधा टन बढ जाये । परन्तु जब हम इन फिगर्ज को देखते है तो हम पाते हैं कि न तो हमारा शूगर परसेंटेज बढ़ा है, न सैक्रोस कंटेंट बढ रहा है इन सैस और न ही पर एकड़ जितना गन्ना पैदा होना है, वह ही बढ रहा है । सन् १९३७–३८ में १४ या १५ टन पर एकड़ हमारे यहां पैदा हुआ करता था और जब जो उत्पादन की फिगर है वह करीब १३ टन पर आ गई है । बाहर की यदि हम फिगर्ज को देखें तो उसका मुकाबला हम नही कर सकेंगे, इस वास्ते उनको कोट करना फिजूल है । जब हमारी यह हालत है कि हमारा जो उत्पादन है उसी को हम ठीक तरह से नही बढा पाते हैं तो बाहर के मुल्कों के साथ मुकाबला करना और यह कहना कि वहां पर इस भाव पर चीनी बिकती है और इस भाव पर गन्ना मिलता है, वहां पर इतना सैक्रोस कंटेंट होता है, ठीक मालूम नही देता है और ऐसा करके हमें निराशा का सामना करना पड़ता है और कुछ दुःख भी होता है, तकलीफ भी होती है । हम तीनों मिल करके कंज्यूमर्स से अच्छी तरह से नफा ले रहे हैं । हमारे भाई कहते है कि शूगर केन के दाम बढ़ने चाहियें । मैं कहूंगा कि जरूर बढ़ने चाहियें । वह १ रु० ५ आने या १ रु० ७ आने कुछ भी कर दिया जाये । किन्तु यदि हम एक एकड़ में जो अभी १३ टन पैदा कर रहे हैं उसके बजाये १८ या २० टन पैदा करने लगें तो जो दाम हमें अभी १ रु० मिलता है उसी में हमको बढ़े हुये दाम के मुकाबले ज्यादा मिल सकता है और ग्रोअर की पर एकड़ इनकम ज्यादा हो जायेगी । इसलिये मेरा कहना है कि यदि

हम केवल यह कोशिश करें देश को बतलाने की कि दाम बढ़ाने से शोरअर ज्यादा लाभ उठायेगा, वह इस तरह से अपना ज्यादा फायदा कर सकेगा और सरकार यदि यही सोचती रहेगी कि हमारे पास जो कर आता है वह मिलता रहे और हम उसे अपने किसी भी काम में लायें, लोगों का इसमें कोई सरोकार नहीं है, तो उससे देश का काम चलने वाला नहीं है। मैं सरकार से, शोअर्स से और शुगर मिल ओनर्स से पूछूंगा कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं? जो चीज आपके हाथ में है उसे तो आप करें। आपके यहां जो दिन प्रति दिन टनेज कम होता जाता है, जो हमारे शुगर केन में सैक्रोज कंटेंट्स हैं वह भी कम होते जाते हैं और जो हमारी रिकवरी है वह भी कम होती जा रही है, आप यह देखिये कि उसका उपाय क्या है। यदि हम उसका उपाय नहीं कर सकेंगे और यदि हम यह नहीं बता सकेंगे कि वह कैसे काम में लाये जायें, यदि हम अपना पर एकड़ टनेज नहीं बढ़ा सकेंगे, १३ टन से १५ या १६ टन नहीं कर सकेंगे तो जैसा हमारे भरूचा साहब ने कहा, कितने दिन तक आप अपना नुकसान कर के चीनी बाहर भेज सकेंगे? कितने दिन तक आप कंज्यूमर्स पर यह भारी बोझा डालते रहेंगे?

जैसा मैंने आरम्भ में कहा कि यह ठीक है कि कंज्यूमर्स पर बोझा पड़ेगा जैसा कि इंडोनेशिया में है, हमारे भाई श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह जी बतला रहे हैं कि वहां चीनी खुले में बिकती है ४८ रु० मन जो कि उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन है, और बाहर वह २० रु० मन भेजी जाती है। यह ठीक है कि ऐसा होना चाहिये, फारेन एक्सचेंज के लिये ऐसा करना ही होगा, लेकिन जैसा भरूचा साहब ने कहा आपको इसकी ओर ध्यान देना होगा। आपने मिलों का एक्सपैन्शन कर दिया। करीब ३८ मिलों के लिये आपने लाइसेंस दिया है और १७ मिलें पब्लिक सेक्टर में रखी हैं।

श्री अ० प्र० जैन: कोआपरेटिव सेक्टर में।

उपाध्यक्ष महोदय: यह पहले पूछ लेना चाहिये था।

श्री झुनझुनवाला: जो कोआपरेटिव सेक्टर है वही पब्लिक सेक्टर है। वह दोनों एक में ही है। चूंकि वह प्राइवेट सेक्टर नहीं है इसलिये अगर वह कोआपरेटिव सेक्टर है तो भी पब्लिक सेक्टर है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मिलों को बढ़ाते हैं। ज्यादा मिलों के बढ़ने से ज्यादा केन पैदा करना होगा। ऐसी हालत में जो हमारी जमीन है जिसमें कि फूड प्रोडक्शन हो सकता था वह शुगर केन की तरफ चली जायेगी। आप अपना काम पूरी तरह से कर सकेंगे या नहीं इसमें हमें सन्देह है, क्योंकि आखिर कितने दिन तक आपके कंज्यूमर्स चुपचाप बैठे रहेंगे? वह बराबर कुछ न कुछ बदले में मांगते रहेंगे। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगर शुगर एक्सपैन्शन करना है तो फैक्ट्री को बना देना तो एक मामूली सी चीज है। आज हमारी सरकार के पास रुपया है वह लोगों को रुपया दे देगी, वह फैक्ट्री बनाने की घोषणा करती रहेगी, परन्तु असली चीज यह है कि जितनी जमीन है उसमें हम कितना ज्यादा पैदा कर सकते हैं। यदि हम उतने में ही अधिक पैदा कर सकते हैं और चीनी को बढ़ा सकते हैं तब तो ठीक है नहीं तो काम चलना कठिन हो जायेगा। हमारे किसी भाई ने इस बात को नहीं कहा। यह तो कहा कि शुगरकेन ग्रोअर्स को ज्यादा पैसा मिलना चाहिये। लेकिन कौन कह सकता है कि वह अच्छी क्वालिटी का शुगरकेन पैदा करते हैं और उसमें सैकाज कंटेंट्स कितने हैं। इसकी ओर आज कोई नहीं देखता लेकिन ग्रोअर्स को दाम जरूर अधिक मिलने चाहियें इंडस्ट्री के लोगों का नफा ज्यादा होना चाहिये पर यह कोई नहीं देखता कि एक्सट्रैक्शन कितना

[श्री झुनझुनवाला]

होता है । मिल का यह काम है कि जो गन्ना उसको दिया जाता है उसमे से वह ज्यादा से ज्यादा चीनी निकाले । मैं माननीय मंत्री जी से पूछूगा कि मिलो में कितनी एफिशिएंसी है और उन्होने अपना काम कहा तक बढाया । सरकार ने, जो कि कर ले रही है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिये, यह देखने के लिये कि पर एकड प्रोडक्शन कितना होता है, उस के सैक्रोज कंटेंटस कितने होते हैं, क्या कार्रवाई की ? और जो कुछ उसने किया उसका क्या परिणाम हुआ ? मै अपने शूगर के ग्रोग्रर भाइयो से भी पूछना चाहूंगा कि आप ने क्या किया जिस से कि गन्ने की उपज अधिक हो सके । बजाय इसके कि आप कल की पैदावार पर डेढ रु० की माग करें, अगर एक एकड में इतनी ज्यादा पैदावार करे कि इस १ रु० के हिसाब से ही आप का ज्यादा पैसा मिल जाय तो अधिक अच्छा है । केवल स्लोगन्स के लिये कह देना कि चलो तुम्हारा १ रु० ४ आ० मन के बजाय १ रु० ८ आ० कर दिया गया उचित नही है । इससे हिन्दुस्तान को कोई लाभ नही होगा । हिन्दुस्तान को लाभ तो तब होगा जब आप की एफिशिएसी बढ़ेगी । और आज शुगर केन में ही मुझे सब से कमी मालूम पडती है । इस में कितना दोष सरकार का, कितना दोष मिल वालों का और कितना ग्रोग्रर भाइयो का है इसे भी तो देखना चाहिये । यदि उन को अधिक पैसा मिल जाता है और अधिक पैसा मिलने से वह इनएफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक से पैदावार नहीं करते, तो इस के ऊपर भी हमको ध्यान रखना चाहिये कि वह एफिशिएंट हों ।

जो शुगर कंट्रोल किया गया है, उस के ऊपर मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि समय नहीं है, केवल यही चीज कहूंगा कि हमारे मंत्री जी ने कहा है कि हम चीनी को किस तरह से बंटवायेंगे । उसके लिये उन्होंने बतलाया है कि हम मिल्स से पर्चेज करेंगे और पर्चेज करने के बाद जो जो लोग इंडेंट देंगे उनके अनुसार उन्हें चीनी देंगे । इसमें एक बड़ा भारी फ्ला है । अभी आपने दाम निश्चित किये है डी २६ के । अब आप यह देखिये कि आप चाहे कोई भी उपाय करें, सरकार कोई तरीका अपनाये, यदि डी २६ सुपीरियर क्वालिटी की शुगर है तो उसके दाम लोग जरूर ज्यादा देंगे और जो इन्फीरियर क्वालिटी है उसका जो कंट्रोल का दाम है वह लेंगे । इसमें बड़े भारी झगड़े की बात हो सकती है और मै सरकार से कहूंगा कि वह इस पर पूरा ध्यान रक्खे और जब किसी को इंडेंट दिया जाता है तो देखे कि उसको किस किस क्वालिटी की चीनी दी जाती है । यदि हम किसी को प्रोव्लाइज करने के लिये उसे अच्छी क्वालिटी की शकर अधिक दे देंगे तो उसका दाम हम कितना ही कंट्रोल करें, वह ज्यादा लेंगे, अगर उन का डी २६ की शुगर दी जाती है तो वह उस का दाम १ रु० २ आ० ही लेंगे जब कि कोई भी चीनी २६ रु० मन की है तो उसका दाम वह १५ आ० भी नही लेंगे ।

जैसा मैंने कहा जिन लोगो को इससे नुक्सान होता है उसकी ओर आप देखिये और जिन लोगो को जो क्वालिटी नही मिलती है वह भी दें । और जो लोग क्वालिटी का फायदा उठाना चाहते है उनको गैरवाजिबी फायदा भी न उठाने दें । और कंट्रोल से जहां आप का कास्ट आफ प्रोडक्शन कम होता है, इसके ऊपर ध्यान रक्खें कि कोई मिल बन्द न हो ।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, चीनी के वादविवाद में मिठास के बजाय अगर थोड़ी सी कड़वाहट आगई है तो उसके लिये सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति जिम्मेवार है । जिन परिस्थितियों में चीनी का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने

अध्यादेश जारी किया, उनके संबध मे खाद्य मंत्री महोदय ने प्रकाश डाला है अगर मुझे यह कहने में बिलकुल भी संकोच नही है कि उन्होंने जो युक्तियां दी हैं और जो तर्क उपस्थित किये हैं उनके द्वारा इस तथ्य का स्पष्टीकरण नही होता कि २७ जून की तिथि ही इस अध्यादेश को जारी करने के लिये क्यो चुनी गई ? उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अप्रैल और मई से इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगे थे कि बाहर से चीनी का निर्यात बढ़ाया जा सके लेकिन अध्यादेश जारी किया गया उस समय जब कि संसद् का सत्र नही हो रहा था। यदि सरकार थोडी दूरदर्शिता से काम लेती तो १० मई को संसद् की बैठक स्थापित होने से पूर्व ही इस संबध मे एक विधेयक उपस्थित किया जा सकता था लेकिन मंत्री महोदय ने कहा कि चीनी का निर्यात करने के लिये जिस तन्त्र की आवश्यकता थी उसके स्वरूप का वह निर्धारण नही कर सकी और इसलिये थोडी सी देर लग गई किन्तु बाद मे जिस एजेंसी के द्वारा जिस तन्त्र के द्वारा चीनी के निर्यात करने का निश्चय किया गया, वह कोई नया अन्वेषण करने पाया कोई नया तन्त्र निकाला गया हो ऐसी बात नही है। चीनी के मिल मालिको को सरकार ने यह काम सौंप दिया जो कि इसके पहले भी इस प्रकार की सेवाये सरकार के प्रति करते रहे हैं।

दूसरी बात जो मंत्री महोदय ने वक्तव्य से स्पष्ट होती वह यह है कि गत वर्ष जब सरकार ने चीनी के निर्यात के लिये कोई विशेष प्रयत्न नही किया था और चीनी के मालिकों ने स्वयं चीनी का निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किया था उस समय १९५७ में १५० हजार टन चीनी बाहर भेजी गई थी और उससे साढ़े बारह करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई थी। इस बार सरकारी प्रयत्नों से जिनके कि परिणामस्वरूप देश में चीनी के दाम अधिक हो गये हैं और उत्पादक और उसके साथ उपभोक्ता दोनो उसका लाभ उठाने से वंचित किये गये हैं। उस समय जब उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं या जिस मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का अनुमान किया गया है, वह तो १९५७ के आकडो से बहुत कम है। सवाल यह है कि जब मिल मालिक स्वय इतनी बडी मात्रा में चीनी का निर्यात कर सकते थे और अप्रत्यक्ष रूप से देश को विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति हो सकती थी तो सरकार ने इस बात की आवश्यकता क्यो समझी कि वह चीनी के निर्यात मे अपना हाथ डाले और वह भी इस ढग से कि जिसमे उपभोक्ताओ के हितो का ध्यान न रक्खा जाय। इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि सरकारी अध्यादेश के परिणामस्वरूप और चीनी के निर्यात के फल के रूप मे देश में चीनी के दाम बढ गये। मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होने चीनी के दामो को बढने से रोकने के लिये कदम उठाये है किन्तु उन्होने यह स्वीकार किया है कि अध्यादेश २७ जन को जारी किया गया था जब कि चीनी के मूल्य पर नियत्रण करने का कदम ३० जुलाई को उठाया गया। मै यह जानना चाहता हू कि इतनी देर क्यो की गई ? क्या सरकार इस बात को सोचने में समर्थ नही थी कि अध्यादेश जारी करते ही चीनी का निर्यात बढाया जायेगा। इस बात के प्रकाश मे आते ही चीनी के दाम बढेगे। हमारे देश के भीतर के बाजार की जो स्थिति है उसमे दामो के बढने की वृत्ति बिलकुल स्पष्ट है और उसे समझने के लिये किसी विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नही है। यदि अध्यादेश जारी करना आवश्यक था सरकार की सम्मति मे जिससे कि मै सहमत नही हू तो क्या अध्यादेश के जारी करने के साथ ही चीनी के दाम देश के भीतर न बढें, इसके लिये कदम नही उठाया जा सकता था लेकिन कदम नही उठाया गया

[श्री बाजपेयी]

और उसका परिणाम यह है कि चीनी के दाम बढ़े है। गांवों में मैंने इस बीच में अपने चुनाव क्षेत्र में दौरा करके देखा है। गांव में १ रुपये ४ आने सेर चीनी बिक रही है क्योंकि आप चाहें एक ही नया पैसा चढ़ायें पर प्रवृत्ति यह है कि वह नीचे की सतह तक जाते जाते अनेक नये पैसे हो जाता है और उस वृत्ति को रोकने के लिये आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिये। वह सरकार ने नहीं उठाया। अब यह सुझाव दिया गया कि चीनी के वितरण के लिये सरकार प्रबन्ध करे। मंत्री महोदय ने सस्ते गल्ले की अनाज की दुकानों का उदाहरण दिया और यह स्पष्ट किया कि गल्ला वितरण करने में इतनी कठिनाईया होती है और इससे आप समझ सकते है कि चीनी का वितरण कैसे सहज सम्भव हो सकता है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार चीनी का दाम बढ़ाने से रोकना चाहती है और जैसी कि उसकी उद्घोषणा है तो इसके लिये जब तक चीनी के वितरण की कई व्यापक व्यवस्था नही की जायेगी जिसके कि अनुसार उपभोक्ता तक उचित मूल्य मे चीनी मिल सके तब तक मै समझता हू कि केवल चीनी के दाम न बढ़े, इस नीयत से चीनी के के दामों का बढ़ना नही रुकेगा। दाम बढ़ रहे है। और उपभोक्ता को इस दृष्टि से क्षति भी पहुच रही है और सरकार उसको दूर करने का प्रयत्न करे, इस बात की आवश्यकता है।

एक बात मै और निवेदन करूंगा। यहां पर गन्ना उत्पादकों की चर्चा की गई है। यह बात स्पष्ट है कि चीनी का निर्यात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा की जो भी प्राप्ति हो किन्तु गन्ना उत्पादक को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ होने वाला नही है। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि हमारे देश मैं चीनी उद्योग का जिस ढंग से विकास हुआ है और सरकार ने जिस बड़ी मात्रा में चीनी उद्योग को संरक्षण दिया है उससे जो चीनी के मिल मालिक है, उनका लाभ अनुपात में अधिक है और गन्ने के उत्पादक का कम है: लाभ नही मिलना चाहिये, ऐसी बात कोई नही कहता है मगर प्रश्न अनुपात का है और यह बात कही गई है कि सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने भी इस तरह की सिफारिश की थी कि अगर चीनी का दाम २६ रुपये प्रतिमन है तो गन्ने का दाम १ रुपये १२ आने प्रतिमन होना चाहिये। आजकल चीनी का दाम क्या है उसे बताने की आवश्यकता नही है . . . .

१५ बजे

श्री च० द० पांडे: उसमें एक्साइज ड्यूटी का भाग भी है।

श्री बाजपेयी: एक्साइज ड्यूटी भरी है। तब शायद ३४ रुपये की होगी। मेरा निवेदन यह है कि उस अनुपात में गन्ने के उत्पादक को लाभ नही मिला। अब सरकार यह आशंका प्रकट करती है कि गन्ने के उत्पादक को अधिक लाभ मिलेगा तो इस बात की सम्भावना है कि गन्ने के उत्पादन का क्षेत्र बढ़ जाय। और फिर गल्ले के उत्पादन मे उसको जोड़ कर यह भय प्रकट किया जाता है कि देश के खाद्यान्न की दृष्टि से यह ठीक नही होगा। लेकिन अगर हम चीनी के निर्यात को प्रोत्साहन देते है और उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की सम्भावना बताते हैं तो फिर इसका यही परिणाम होगा और इसको रोका नही जा सकता कि गन्ने के उत्पादन को और प्रोत्साहन मिले। मैं समझता हूं और सेठ झुनझुनवाला ने ठीक कहा है कि जो भी गन्ने के उत्पादन का क्षेत्र है उसी में हमें अधिक से गन्ना पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिये, मगर इसके लिये भी गन्ने

के उत्पादकों को जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वे नहीं प्राप्त हैं। मेरे अपने क्षेत्र का मामला है। बांधों को बड़ी बड़ी योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है, और जो पहले सरकार ने ट्यूब वैल बनाने का वायदा किया था बलरामपुर और तुलसीपुर के क्षेत्र में वे ट्यूब वैल भी बने नहीं हैं। इसके कारण वहां पर गन्ने के उत्पादन का क्षेत्र कम हो रहा है। यह वस्तुस्थिति वहां है, भले ही सम्पूर्ण देश में इसको लागू न किया जा सके। इस बात की आवश्यकता है कि चूंकि किसान को गन्ने का उत्पादन बढ़ाना है इसलिये उसे आवश्यक सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें, जो करने में सरकार सफल नहीं हो सकी है।

मैं समझता हूं कि अध्यादेश को जारी करने के जो भी कारण बताये गये वे पर्याप्त नहीं है। शासन या तो पिछले संसद् के सत्र के समय इस प्रकार के विधेयक को उपस्थित कर सकता था या वर्तमान सत्र के लिये प्रतीक्षा कर सकता था। लेकिन मिल मालिकों के कहने पर उसने एक अध्यादेश जारी किया जिसमें गन्ने के उत्पादकों और चीनी के उपभोक्ताओं दोनों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। अगर चीनी के निर्यात में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है तो उससे किसी को विरोध नहीं है लेकिन मन्त्री महोदय को यह स्पष्ट करना चाहिये कि जब गत वर्ष सरकार की किसी सहायता के बिना चीनी के मिल मालिकों ने १५० से १६० हजार टन चीनी का निर्यात किया और साढ़े १२ करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की, तो इस बार आगे बढ़ कर सरकार को उसकी सहायता करने का क्या कारण है।

इससे अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, कई मित्रों ने अध्यादेश जारी करने पर आपत्ति जाहिर की है। लेकिन मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि कुछ दोस्तों की तो नीति ही यही है कि अध्यादेशों का विरोध किया जाये। कुछ लोगों ने कहा है कि सरकार ने मिल मालिकों के दबाव में यह अध्यादेश जारी किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार ने किसी खास मतलब से ही इसे जारी किया है। इस सरकार ने जब अखबार के मालिकों के दबाव में अध्यादेश को नहीं रोका फिर इस सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि चीनी के मिल मालिकों के दबाव में आकर उसने यह अध्यादेश जारी किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अखबार से तो मिल ज्यादा भारी होती है।

चौ० रणवीर सिंह : तो मैं अर्ज कर रहा था कि बात दर असल क्या है। अध्यादेश जारी करने पर मैं भी आपत्ति कर सकता था अगर मुझे यह पता हो कि मेरे नायक दोस्त जो आपके बायें बाजू बैठे हैं उनमें इतनी शक्ति है कि जो विधेयक सरकार लाये या जो अध्यादेश जारी करे उसे वे नामंजूर करवा सकते हैं।

श्री बजराज सिंह : उस वक्त तो सरकार इधर आ जायेगी।

चौ० रणवीर सिंह : वह तो आपका अन्दाजा है।

सचाई तो यह है कि आज सरकार जिस विधेयक को लाती है, वह पास हो जाता है चूंकि सरकार के साथ जनता का विश्वास है और संसद् के सदस्यों का विश्वास है। इसलिये अध्यादेश जारी करने पर जो आपत्ति है वह मेरी समझ में नहीं आती।

कई दोस्तों ने इस विधेयक और अध्यादेश पर बड़ी आपत्तियां जाहिर की हैं। मुझे भी कुछ आपत्ति हो सकती है। लेकिन

[चौ० रणबीर सिंह]

एक बात मुझे बहुत साधारण सी दिखायी देती है जिसको बहुत पेचीदा बनाने की कोशिश की गयी है। साधारण बात यह है कि इस देश में पिछले साल इतनी चीनी पैदा की गयी थी कि डेढ़ लाख टन चीनी बाहर भेजी जा सकी। मेरे एक दोस्त ने यह बतलाने की कोशिश की कि साहब इस साल पैदावार कम है। यह ठीक है। अगर इस कमी का अन्दाजा न लगाया जाता तो मैं समझ सकता था कि सरकार की तरफ से कोई गलती हुई है। लेकिन उस कमी का अन्दाजा लगा लिया गया है। सरकार ने केवल ५० हजार टन भेजने का फैसला किया है। अगर इस साल की पैदावार का अन्दाजा ठीक है तो हम एक लाख टन तक भेज सकते थे। लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया। उसने यह ख्याल रखते हुये कि बाहर चीनी भेजने से कोई खराबी न हो, और आबादी की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुये केवल ५० हजार टन भेजने का फैसला किया है और उसके लिये यह विधेयक लाया गया है। जहां तक इस बात का वास्ता है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती।

लेकिन एक बात है कि यहां व्यापारी वर्ग है और जिसको मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास कहा जाता है उसमें से बहुतों का दिमाग इस बात पर लगता है कि किसी न किसी तरह से, किसी कानून से कोई नाजायज फायदा उठाया जाये और जो गरीब का हक है उसे छीना जाये। यही कारण है कि चीनी के भाव बढ़ गये। इसका और कोई कारण नहीं है। जब पिछले साल डेढ़ लाख टन चीनी बाहर भेजी गयी तो भाव नहीं बढ़ा फिर आज ५० हजार टन के कारण ही कौनसा भारी वजन आ गया कि जिसकी वजह से भाव बढ़े।

मैं उन लोगों का मशकूर हूं कि जिन्होंने किसानों के लिए दो चार बातें कही हैं। जो बात शुगर केन ग्रोअर्स के हक में कही गयी है मैं उससे सहमत हूं। लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि डिमांड और सप्लाई का सवाल है। अगर शुगर बाहर न भेजी जाये तो उसका भाव यहां बाजार में गिर जायेगा और उसका नतीजा यह होगा कि अगले साल के सीजन में शुगर केन ग्रोअर पर उसका असर पड़ेगा। यह तो एक मामूली बात है। आज हम जिस इकानमिक उसूल के तहत चल रहे हैं यह कदम तो उसके तहत ही उठाया गया है। लेकिन सरकार की एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। सरकार जानती है कि इस देश का बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग और कारखानेदार वर्ग का हिस्सा कितने ईमानदार हैं। इस लिए इस सिलसिले में उस को कुछ सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। ऐसी हालत में मैं यह समझने में मजबूर हूं कि उन कारखानेदारों के जिम्मे यह क्यों छोड़ा गया है कि वे एक्सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि वे लोग एक बड़ी अच्छी रोजी पिक्चर हमारे सामने रखें और कहें कि वे यह काम नो प्राफिट नो लास के बेसिस पर करेंगे—उतनी कटौती करेंगे, जितना कि खर्च होगा। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि कौन इस बात का पता लगायेगा कि कितने अफसर रखने चाहिएं और कितने रखे गए हैं। यह भी मुमकिन हो सकता है कि उस संस्था में कारखानेदारों के रिश्तेदारों को भर दिया जाय और खर्चा बढ़ा दिया जाय और हमारे देश की जो बाहर तरह को-आपरेटिव मिल्स हैं वह खर्चा इनडायरेक्टली उन पर पड़े। आखिर इस की जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने उन लोगों पर विश्वास करने का क्यों सोचा है। और फिर वे कौन दोस्त हैं? आज से दो साल पहले फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी में मई, जून में यह बताया गया कि इस देश में चीनी बहुत ज्यादा

और उस को एक्सपोर्ट किया जायेगा, लेकिन उस के डेढ़-दो महीने ही बाद ही इस देश में चीनी की कमी को जाहिर किया गया और सरकारी तौर पर पचास हजार टन की इजाजत दी गई, जैसे कि आज दी गई है। इस देश के व्यापारी वर्ग और कारखानेदारों की यह हालत है कि एक नया पैसा बढ़ने पर कन्ज्यूमर के लिए तीन रुपए का इजाफा होता है। इस में सरकार की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहां के लोगों की है, या व्यापारी वर्ग की है।

मेरे दोस्त श्री झुनझुनवाला ने कहा कि सब कहते है कि काश्तकार को और पैसा दो, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि काश्तकार ज्यादा क्यों नहीं पैदा करता, ऐसी फसल क्यों नहीं पैदा करता, जिस का सूक्रोस कन्टेन्ट ज्यादा हो। श्री रंगा इस सबजेक्ट के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा और श्री वाजपेयी ने भी कहा कि अगर शुगर एक्सपोर्ट करेंगे, तो गेहूं के बोने पर उस का असर पड़ेगा। थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि काश्तकार की कुछ लिमिटेशन्ज होती हैं कि कितनी ईख पैदा कर सकता है, कौन सी जमीन में ईख बोनी चाहिए, जो कि उस के लिए और देश के लिए फायदेमन्द हो। इस मामले में कहना और प्रचार करना तो बड़ा आसान है। बड़े व्यापारी, सेठ साहूकार यह भूल जाते है कि मार्जनल प्रोडक्शन के लिए फालतू खर्च चाहिए। हर चीज के लिए, जिस की कि आप मार्जनल प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप गुंजायश रखते है, आप का इकनामिक्स गुंजायश रखता है, लेकिन यह उम्मीद रखते हैं कि काश्तकार ऐसे ही एक एकड़ में एक मन, एक टन बढ़ा दे। आप जरा इस बात पर गौर करें कि कितना रुपया आप ने उस की मदद के लिए दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस हाउस में सही तौर पर उस बारे में गिला किया गया है।

गुजरात के एक साथी से मेरी बात-चीत हुई, जो कि पंजाब जा रहे थे। मैंने उन से कहा कि आप को पंजाब और गुजरात में क्या फर्क दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि शायद यहां पर कुछ इन्सान की और कुछ भगवान की मेहरबानी है। मैंने उन से कहा कि गुजरात के मुकाबले में शायद पंजाब के ऊपर भगवान की उतनी मेहरबानी नहीं है, जितनी कि इन्सान की मेहरबानी है, इसलिए कि यहां पर खेती के लिए ज्यादा रुपया लगाया गया है। अकेले भाखरा डैम पर इरीगेशन बढ़ाने के लिए १२० करोड़ रुपया लगाया जायागा। कुदरती बात है कि आप खेत में जितना लगाना चाहते है, उस के मुताबिक ही आप को मिलेगा—जितना गुड़ आप डालेंगे, उतना ही मीठा होगा। गुड़ नहीं डालेंगे, तो मीठा नहीं हो सकता है प्रचार चाहे आप कितना करते फिरें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप शुगर से पीछे गुड़ की तरफ चलने लगे हैं।

चौ० रणबीर सिंह १९५३-५४ में शुगर बहुत बड़ी मिकदार में आयात होती रही। इस मन्त्रालय के कुछ विशेषज्ञ सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इस देश के किसानों ने इतना गन्ना पैदा किया कि गुड़ आठ रुपए मन पर भी नहीं उठा। एक वक्त था कि किदवई साहब सोचते थे कि गुड़ से चीनी बनायेंगे, तो यू० पी० का किसान बचेगा। इस देश में उन्हीं किसानों के रहते हुए बाहर से चीनी आई। पिछले साल हम ने बाहर चीनी भेजी और आज भी बाहर भेजने के लिए मजबूर हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि यह ठीक है कि यहां के किसान बहुत बड़ी तादाद में अनपढ़ हैं लेकिन फिर भी उन को कुछ समझ है। आप जरा आंकड़े देखिए। १९५६-५७ में गन्ने और चीनी की पैदावार बढ़ी, गुड़ की पैदावार बढ़ी। क्यों? उस की वजह यह है कि १९५३,

[चौ॰ रणबीर सिंह]

१९५४, १९५५ में गेहूं के दाम गिरा दिए गए और गेहूं नौ रुपए मन नहीं बिका। किसान समझता है कि आप उस की इमदाद नहीं करते हैं, उस को रुपया नहीं दिलाते हैं। यह देख कर वह कम से कम जान बूझ कर भूखा मरने के लिए तैयार नहीं है। ज्यादा न सही, कम सही, लेकिन उस के पास जितनी भी समझ है, उस को वह इस्तेमाल करता है। मुझे पता नहीं कि इस मंत्रालय के विशेषज्ञ और प्लानिंग कमीशन के लोग यह सोचते हैं या नहीं कि इस देश में एक साइकिल बन गई है। हम जानते हैं कि १९४७ के बाद इस देश के किसानों ने इतनी मिकदार में गन्ना, कपास और पटसन और दूसरा गल्ला पैदा किया, जितनी कि यहां जरूरत नहीं थी। मुझे वह दिन याद है कि मंत्री महोदय ने कहा कि उन के पास कोई मशीनरी नहीं है, जो कि किसानों के गेहूं, धान और बाजरे वगैरह को खरीद कर रख सके, उन के पास इस काम के लिए रुपया और गोदाम नहीं है। मंत्री महोदय को मालूम है कि उस स्टेट में, जहां शूगरकेन पैदा होता है, आज गेहूं बीस, बाईस रुपए मन के हिसाब से बिक रहा है? इसका असर आज तो नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगली फसल में आप उस असर को नहीं रोक सकते हैं। गुड का आज जो भाव है, उस का असर इसी सीजन में पड़ने वाला है। वह ज्यादा गुड पैदा करने की कोशिश करेगा और मिलों को कम से कम देने की कोशिश करेगा।

15.22 hrs.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

अगर एक पैसा भाव बढ़ने से तीन रुपया मन बढ़ा दिया जाता है और पंजाब-यू॰पी॰ के बार्डर पर एक मील इधर पांच रुपए मन कम गेहूं बिक रहा है और एक मील उधर छः रुपए मन ज्यादा बिकता है और इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो मुझे यकीन है कि आप में जितनी भी शक्ति हो, किसान कितना ही ग़रीब हो, लेकिन इतना तो वह भी कर सकेगा कि जब गुड़ से उस का फायदा होता है, तो वह गुड़ बनायगा और आप उस को रोक नहीं सकेंगे। इस का नतीजा यह होगा कि आने वाले साल में आप को चीनी इम्पोर्ट करनी पड़ सकती है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अगले साल भी चीनी का उतना ही उत्पादन हो जितना इस बार हुआ है या आप यह चाहते हैं कि वह और भी अधिक हो तो आपको चाहिये कि आप शूगर केन की प्राइसिस को बढ़ायें। अगर आपने शूगर केन की प्राइसिस को नहीं बढ़ाया तो मैं आपको आज ही चेतावनी देना चाहता हूं कि आठ महीने के बाद आप देख लेंगे कि शूगर की जो पैदावार है वह इसी फसल में गिर जाए गी और उसके बाद अगली फ़सलों में और भी गिर जाएगी। अगले साल आपके पास जो एक लाख टन चीनी है उसके एक्सपोर्ट किये बगैर यदि आपने काम चला लिया तो ठीक लेकिन अगर आप उसके बगैर काम नहीं चला सके तो खाण्ड की कमी महसूस हो जायेगी। जो इलाका इस वक्त शूगर केन उगाने में आता है उसमें से जितना गेहूं उगाने में जा सका चला जाएगा और इसका नतीजा यह होगा कि जिस तरह से आपको सन् १९५३-५४ में करोड़ों रुपये की शूगर बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ी थी, उसी तरह से आगे भी दो तीन साल में आप इम्पोर्ट करने पर मजबूर हो जायगे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद-बिहार) : गेहूं तो सस्ता हो जायगा।

चौ॰ रणबीर सिंह : गेहूं भी सस्ता नहीं होगा।

Shri Ghosal (Uluberia): For the whole day, we have been used to

bitter words in a sugar debate. (*An Hon. Member*: *Sugar- coated*).

At the ouset, the purpose of the Government seems to be very innocent, namely, to boost up sugar exports so as to earn foreign exchange. But if we give serious thought to the provisions of this Bill and the purpose for which Government have introduced this Bill, we shall find that there are many difficulties we shall have to face later on.

It is true that in one year Rs. 12 crores of foreign exchange were earned by sugar exports. This also occupies the fourth place in the export trade list. But that cannot be the single reason for pushing our sugar into the foreign market, because it has already been said that we shall have to incur a loss of 8 annas per maund which is estimated at about Rs. 1·40 crores, which has to be borne by the industry without any corresponding rise in price in the internal market. But in our experience, we have found that as soon as an Ordinance was promulgated, the price of sugar went up by one anna per seer. The Government have argued that the price of sugar has been controlled; at the same time, when consumers go to the market to purchase sugar, they find that the price has risen. Government have already pleaded their helplessness. The hon. Minister of Food has said that we have got no machinery to see that articles are sold at control rates. So the control rates are in the interest of the big businessman who gets the articles he wants at those rates, whereas there is no machinery to see that the consumer gets the articles at control rates.

If the price of sugar rises, who will be affected most? From statistics published in the July issue of *Indian Sugar*, we find (page 258):

> "The two lower-income groups (Rs. 1 to Rs. 100 and Rs. 101 to 175) account for nearly 83 per cent. of all families and about 72 per cent. of the entire sugar consumption in value terms".

So the lower group and the middle class group of persons will be most affected by the rise in the price of sugar. I apprehend that the millowners also will try to make up for the shortage in their profit by increasing the price in the internal market. We find in the editorial of Indian Sugar I have already referred to:

> "Sugar prices in the world market are in a depressed state. Exports of Indian sugar have, therefore, to be *effected* at a *price* much lower than that obtaining in the country. This, of course, is not a thing particular to India, as many of the world's exporting countries have to sell their sugar to the export markets at a much lower price, and the resultant loss is made good by pushing up the internal prices".

So the bad effect on the internal prices will ultimately affect the economy of the ordinary people.

It is of course a riddle to us as to what is the price in the world market. Sometimes we are informed that the price in the world market is lower than that obtaining here. But on page 289 of the same journal it is stated:

> "During the month of June, there was moderate business in Raws as well as Whites. But there was no particular pressure from sellers which would have affected the overall steadiness".

We do not know what is the actual condition in the world market at the present moment.

As regards production, we know that under the Second Five Year Plan, the production target, by 1960-61 is fixed at 780 lakh tons as against the actual production at the end of the First Five Year Plan of 580 lakh tons, that is, by 1955-56. This production has increased in 1956-57, that is, in the first year of the Second Plan, to 669 lakh tons. The estimate for 1957-58 has not yet been

[Shri Ghosal]

obtained. But the increase in production is not due to increase in the yield per acre, but due to the increase in the acreage under cultivation. This is a disadvantage because when we want to increase production of foodgrains, we should not divert cultivable lands where foodgrain cultivation can be undertaken to sugarcane cultivation; otherwise, we would be decreasing the total cultivable lands under foodgrains. It has also been accepted by the hon. Minister that it is not a healthy sign.

A survey was made by the U.N. Expert and he said that we can increase the yield per acre of sugarcane from 30 to 50 per cent. and that due to want of irrigation and other facilities the yield is not being increased. I would draw the attention of the hon. Food Minister to this so that the question of increase in yield may be taken up

It has already been asked by many of the hon. Members how long is this policy of selling our sugar at a loss in the foreign markets and purchasing our foodgrains by spending the foreign exchange earned to be continued, and whether it is a long-term policy or a short-term policy. As a long-term policy it is not good economics, as has already been pointed out by Prof. Ranga.

As regards the export agency, I would like to submit that the State Trading Corporation should have been made the agency. Of course, the Deputy Minister said that the hands of the Commerce and Industry Minister are now full and they cannot take this up That was said on the 7th May in reply to a question. I should say that it is not a convincing reason for not giving the agency to the State Trading Corporation. My submission would be that it should be given to the State Trading Corporation instead of to the Indian Sugar Mills Association.

Lastly, I would like to submit that if Government want to earn foreign exchange by selling sugar, they must at least maintain co-ordination between these things, namely, (1) proper price is obtained by the cane growers, (2) proper wages are obtained by the workers and (3) proper price is maintained for the consumers. If this co-ordination is not maintained, it will not be possible to earn foreign exchange; or, if that foreign exchange is earned, it will not be available for any good use to our country.

Shri Satyendra Narayan Sinha: Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Bill moved by the hon. Minister of Food and Agriculture and to oppose the Resolution of my hon. friend Shri Braj Raj Singh. Even Shri Braj Raj Singh has not adduced any very cogent reason for accepting his Resolution disapproving the Ordinance promulgated by Government. He also feels that it is necessary to export sugar this year as well despite the fact that the world price is much lower than our internal price. So, he agrees with the principles of the Bill; he agrees with the purpose of the Bill; but, he has objection only to the promulgation of the Ordinance. And, he felt that before promulgating the Ordinance the hon. Minister should also have seen that the millers did not take advantage of the speculative price According to him, perhaps, Rs. 3½ crores have already been mopped up by the millers by charging Rs. 2 per maund higher than the prevailing price.

I should have expected the hon. Minister to enlighten the House on this point. In fact, it is a very material point. If the millers have already made a profit of Rs. 3½ crores, then, the case for any kind of subsidy or any kind of increase in the internal price loses its legs. So, I would request the hon. Minister, while replying to the debate, to kindly enlighten this House on this point.

As far as the purpose of this Bill is concerned, I have found that there is hardly any difference of opinion in this House except, perhaps, on the part of one or two hon. Members. Even Shri Braj Raj Singh agrees that it is necessary to export sugar. We are having a policy of expansion of the sugar industry. The Planning Commission has already set a target of 2·5 million tons to be achieved during the Second Five Year Plan; and licences for expanding 59 existing units have already been issued. And, it is proposed to set up 50 new units.

You will notice that at the rate at which the productive capacity is being increased, not only will the target of 2·5 million tons be reached but it will be exceeded by a big margin. Our offtake for internal consumption has not gone so far beyond 19 lakh tons or so. Even if we allow a little more increase in the offtake, there will be quite a good margin of carry over. So, we need some sort of flow or outlet for this extra production. If we are not going to provide some sort of safety valve by resorting to exports, the result would be that there will be glut in the internal market resulting in the closure of mills and unemployment, hardship and distress to cane growers and all that. So, it is necessary that we should continue the practice of exporting some sugar every where.

Last year, as has already been said, we exported 1·53 lakh tons and the result was that already a scare was created in the international market. I have seen in an article that the Chairman of a British firm already expressed his fear that the Indian sugar export constituted a big threat to the U.K. What was gained last year should not be lost this year by stopping exports altogether. Therefore, I wholeheartedly support the purpose with which this Bill has been brought forward.

My friend, Shri A. C. Guha, while asking the hon. Minister of Food and Agriculture to examine the cost structure expressed surprise why we could not export again this year 1·5 lakh tons when we did so last year. Likewise, some other hon. friends—Shri Vajpayee I think—have also made this point. But the hon. Minister, while introducing the Bill, told the House that we are exporting 50,000 tons of sugar this year. The result would be that we would be losing about Rs. 1·40 crores. If we spread it over the total internal production, the loss per maund will be 50 naya paisa per maund or 1·0 naya paisa per seer. If we have to subsidise the internal sale, the consumer would not suffer more than one naya paisa. Really the apprehension expressed by our friends here in opposition to this measure is that it will operate as a great hardship to the ordinary consumers. Government has controlled the ex-factory prices but no step has so far been taken to control retail prices. The hon. Minister has said that there are about two lakh retail shops and perhaps the machinery is not adequate to regulate the sale. I would plead with the hon. Minister that the real fear expressed by the hon. Members here is that the hardship that will be caused will be passed on to the ordinary retail consumer. So, it is necessary to have some control of the retail prices.

Shri Ramji Verma has said that the production has come down this year by 59,000 tons and has suggested that the internal consumption will be less by that quantity. He forgets that there is already a carry over of 4·5 lakh tons and we expect that even after having exported 50,000 tons there will be a carry over of about four lakh tons. Actually, even if we export a lakh tons, there will be a carry over of 3·5 lakh tons. which is 15 per cent. of our total consumption. Perhaps the only reason why the hon. Minister is not increasing the export quota is that it will mean more hardship to be spread over and perhaps he will have to resort to a much greater subsidy.

[Shri Satyendra Narayan Sinha]

So far as the export of sugar is concerned, I am at one with the hon. Minister that we should continue the export of sugar and capture the market. So long, we have been depending on three items: jute, tea and textiles. It was said that we could have earned this foreign exchange by increasing the export of tea. But we have got to diversify the export trade also. We should not depend upon traditional items so that if there is some difficulty in production either here or in the world market, there is some instability in the balance of payments. So, it is necessary to introduce some more items in our export trade. From that point of view, I think Shri Naushir Bharucha will also withdraw his objection and agree that it is necessary to continue the good work that we did last year and create a market for our sugar in the foreign countries. As I have already indicated, in course of time, we will be producing enough sugar in this country and if we are not having some sort of an outlet, there will be a glut in the internal market and it will mean a still greater hardship.

I whole heartedly support my hon. friend Shri Jhunjhunwala when he says that while we are resorting to all these measures, it is necessary also to look into the cost structure of our industry. This is a valid point and we cannot continue to go on exporting at a loss altogether. He has referred to Indonesia; it is producing eight lakh tons and is exporting half of it at Rs. 20 per maund whereas her internal price is about Rs. 48 per maund. Yet it is not good economics if we continue the export at a loss. Therefore, it is necessary from our point of view that we should do our best to try to increase the yield of sugarcane per acre. Government are aware of this need and they are taking steps but it is necessary that they should do it sooner, so that the results are felt in the country. We should also try to increase the sucrose content. Unless we make it a profitable proposition, it is no good taking emergency measure. Ultimately, we will not be able to sustain this export trade with this high cost structure in the country.

The whole aspect of the sugar industry has been discussed in the course of a small measure, which I think was not necessary and the question of sugarcane growers has been brought in. We do feel that some sort of a relationship should exist between the cost of sugarcane and the price paid. It was decided by Dr. Katju when he was Industries Minister in U.P. that this kind of a relationship should exist but this has not been given effect to so far.

What is needed is that we should vigorously take up this question of reaching to the ordinary farmer the results of our experiments in the research laboratories and institutes and see how far these experiments bear fruits.

Before I conclude I want to underline once again this point that we must give further attention to this aspect of the question. With these words, I wholeheartedly support the measure before this House.

Shri A P. Jain: Mr. Chairman, some hon. Members have accused me of showing partiality to the millers and of showering on them undeserved encomium. This is far from true. I have been as critical of the millers as I have been paying them their due praise. All that I said was that the Indian Sugar Mill Association has done a good service in exporting more than 150 thousand tons last year. I also said that some of the millers had failed to abide by the assurance which they gave which compelled us to control the price of sugar.

Two hon. Members, Shri Ranga and Shri Naushir Bharucha, are opposed to the basic objectives of the Bill. Shri Bharucha has said that we have selected a wrong commodity. My hon. friend, Shri Satyendra Narayan

Sinha has made my task easier; he has very correctly said that we should try to as much broad-base our exports as we possibly can. I may tell Shri Bharucha that the future pattern of our Indian foreign trade is going to be very different from what it is today. We should try to step up the export of tea, jute and textiles but that is no reason why we should not export sugar in ever larger quantities. Past experience has shown that we can export sugar and it is going to be our definite policy to export sugar. We shall try to create suitable conditions for exporting sugar.

One question has been raised by more than one hon. Member: Shri Panigrahi, Shri Guha and Shri Vajpayee. They have stated that on the last occasion in 1957, the Indian Sugar Mill Association could export more than 150 thousand tons of sugar on their own account. Then, why not they do it today, they ask. The fact of the matter is that even last year, 1957, we prepared a scheme and assisted the Association in making arrangements for the export. But the circumstances prevailing at that time were very different from what they are today. In my opening speech, I said that in 1957, as a result of the Suez crisis and also as a result of the failure of the beet crop in Europe, the world price of sugar had gone up and so we could export sugar and make a little profit. This year the position is different. Our internal prices of sugar are higher than the world prices, and, therefore, we have to export sugar at a sacrifice. That is one reason why it has become necessary for Government to enact an Ordinance first and now an Act, because we had to devise a method for financing the loss and for that a law is necessary. That is the justification as to why we passed the Ordinance.

Different opinions have been expressed on the need for enacting the Ordinance. On principle, I have no difference. Ordinance is something extraordinary and it is only in exceptional cases that Government should take recourse to Ordinance. That was exactly the position. Because we are badly in need of foreign exchange, we passed the Ordinance.

A fundamental question has been raised, whether it is a good policy to export sugar at a loss.

Shri Naushir Bharucha: At a huge loss.

Shri A. P. Jain: Yes, I am prepared to accept that also, a huge loss. That depends upon the conditions. We are badly in need of foreign exchange. It is not only we who are exporting sugar at quite a heavy loss, but some other countries who are similarly situated and who are in need of foreign exchange, for one reason or the other, are also doing so. The case of Indonesia has been mentioned. Another case is that of Australia, where the internal prices are much higher than the prices at which they are exporting sugar.

Well, it is a good suggestion, a nice suggestion that we should make every effort to bring down the cost of production, and one of the ways of reducing the cost of production is that each acre under sugarcane should produce much more than what is produced today. That is the one solution of the sugar industry. Unfortunately, our sugarcane yields are very low, some of the lowest in the world. It is not so all over the country. In the south the sugarcane yields are much higher, as much as 50 to 60 tons per acre, as against 11 to 13 tons in northern India. That is partly due to climatic reasons. But I think even the disadvantages attaching to climate can be overcome to a large extent, and it should be an effort on our part to increase the yield per acre.

That also answers the question which has been raised by a number of hon. Members, that the export of sugar has the greatest potentialities of encroaching upon the foodgrain area. The other day, while discussing the

[Shri A P. Jain]

question of foodgrains versus cash crops, I made it clear that it is the definite policy of the Government of India to see that larger production of cash crops should be obtained by intensive cultivation and not by encroachment on the foodgrain area We shall make every effort to achieve that end

A question was raised by Shri Ranga as to whether we have been able to control even the wholesale prices He said that many of the wholesalers are in one or another way connected with the millers, and he was doubtful whether we have been able to control the wholesale prices Now, our mechanism is something like this One-fourth of the entire production of sugar in a year is earmarked for being requisitioned by the Government This year the production was a little less than 20 lakh tons, and so we are entitled to requisition five lakh tons of sugar We have prescribed the control price for that sugar, and we have got the power to sell the sugar earmarked for requisition at the control price to anybody whom we authorise to buy We are selling sugar in quantities of one wagon and more Our sales are not confined to the existing wholesalers Anybody who wants to trade in sugar can put in an application to the Government that he wants one wagon of sugar We then order the mill to supply him one wagon of sugar at the control price, and he buys the sugar and sells it So the area of competition is now enlarged, it is no longer confined to the traditional wholesalers

I dare say, Sir, that as a result of this operation, we have met with almost full success On 3rd of May, at Jullundur the price of sugar was Rs. 37-20 n P—that is the wholesale price. On the 26th of July, the price went up to Rs. 39-22 n.P. Then we undertook this new sale operation and the price has been brought down—I am giving the figure as on 13th of August—to Rs. 37-12 n.P.: that is, a little lower than what it was on 3rd May, and all the rise has been eliminated In Delhi, on the 3rd of May the price of sugar was Rs. 38-31 n.P. On 26th July, it went up to Rs 40-25 n P Now it has been brought down to Rs 38—a little lower than what it was on 3rd May Similarly, in Kahpur the price on 3rd May was Rs 36-78 n P It went up to Rs. 38 on 26th July Now it has been brought down to Rs 37 Similar is the tale with regard to other places

Shri Panigrahi: How do these prices compare with ex-factory prices fixed by the Government on 30th July?

Shri A P Jain: There was no fixation of price on 30th July, but I can say that the ex-factory prices had also gone down

Shri Panigrahi: On the notification of 30th July the ex-factory prices were given

Shri A. P Jain: I shall give the ex-factory prices also On 22nd July, the ex-factory price in Punjab was Rs 38-52 n P and now it is Rs 36-50 n P In Western U P, the ex-factory price on 22nd July was Rs 37-87 n.P. and now it is Rs 36

Shri Braj Raj Singh: What were the prices at the time of the promulgation of the Ordinance?

Shri A P Jain: I am giving the figures as on 22nd June In the Punjab, it was Rs 37-38 n P and now it is Rs 36-50 n P In Western U.P., it was Rs 36-61 n.P and now it is Rs 36 In Eastern U P., it was Rs. 36-13 n P and now it is Rs. 36. In North Bihar, it was Rs. 37-25 n.P. and now it is Rs 36

Seth Achal Singh (Agra): What about Delhi State?

16 hrs.

Shri A. P. Jain: Delhi State has no factories. Our control measures, I

submit in all humility, have been effective.

Shri A. C. Guha raised a question as to why we have not entrusted this export business to established shippers. He said that that is the normal practice. Now, there is a little misunderstanding about the export of sugar. If a large number of Indian sellers go into the foreign market and begin to compete with one another, our prices go down. Nearly all the countries which are controlling exports or which want to promote export, raise their export through a specialised agency. The question is what should be the specialised agency. A difference of opinion has been expressed, and some hon. friends have said that it should not have been the Indian Sugar Mills Association but that it should have been the State Trading Corporation I have already stated that the State Trading Corporation is very much in our mind We asked the State Trading Corporation to take it over. Their hands are full and they have no experience of sugar. Therefore, we have selected this agency and this agency will operate on a no-profit-no-loss basis We shall take care that nothing wrong happens and I am hopeful that it will give fruitful results.

Another hon. Member, Shri Naushir Bharucha, said that we have undertaken this export because there was unutilised capacity of the industry and that the industry wanted to make profits by producing more, part of which would be exported and part of which would be internally consumed. I am sorry to state that these facts are not correct. It has nothing to do with the rated capacity In fact, the rated capacity today is lower than what the sugar industry is producing, and, therefore, there was no question of utilising any unutilised capacity

Shri Naushir Bharucha: May I know how many factories actually worked last year?

Shri A. P. Jain: I am sorry I can not give the figure, but it may be of the order of about....

Shri Naushir Bharucha: Out of 202, about 75 per cent. only worked.

Shri A. P. Jain: No, no. All the factories that were capable of working were working.

Shri Naushir Bharucha: 158 out of 202.

Shri A. P. Jain: Shri Jhunjhunwala has raised a rather pertinent question about the cost structure of sugar. In fact, there is dissatisfaction among the millers on the control price that we have fixed. On the other hand, some questions have been raised here, that we are giving them too much of profit. I am prepared to consider the question of making a reference to the Tariff Commission who may look into everything and then give their verdict which, I think, will be fair to everybody concerned.

Shri Braj Raij Singh: That should be done!

Shri A. P. Jain: Lastly, I am grateful to the hon. Member, Shri Satyendra Narayan Sinha, who has answered many of the questions which were raised by other hon. Members. He asked me to explain whether caution was taken to avoid rise in prices at the time when we brought out the ordinance. That was the question he put. We did take care. We examined the trend of the prices and we found that during the past two months, since the news about export went about in the market, there has been an upward trend. In some places, there was a rise of 12 annas and in some other places, a rise of one rupee; in other places, a little more and in some other places, a little less. We came to the conclusion that the export of 50,000 tons will involve a loss of eight annas per maund. Now, we told the millers that their price had already gone up and they should be able to absorb this loss of eight annas in the price which had already been attained. They gave us an assurance that the mills will not raise the ex-factory prices. Some of the mills

[Shri A. P. Jain]

continued to sell at the old prices. Others did not abide by that assurance.

Now, the next thing that we did was, in order to overcome this difficulty, to release a quota of 1,70,000 tons in the middle of July. We also took some steps by way of limitations of credit advance. Some of the millers again withheld the quota. They did not care to sell the quota which we had released, and therefore, we were driven to the necessity of controlling the price. We were not happy with it; but we were quite angry with it. But there is no option. The default is theirs, because they gave an assurance and they did not abide by that.

These are some of the questions that have been raised and on the whole I find that while there has been a discordant voice raised by two hon. Members, this Bill in general has received the support of the hon. Members. I hope they will give their acceptance to it.

श्री बजराज सिंह : सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है कि इंडियन शुगर मिल्ज एसोसियेशन को चीनी के निर्यात का काम सुपुर्द करते समय खाद्य मंत्री महोदय को यह कहने की जरूरत पड़ी कि निर्यात के लिये उन्हें एक मशीनरी खड़ी करनी थी और इसलिए यदि वह लोक-सभा के अधिवेशन की प्रतीक्षा करते, तो वह मशीनरी खड़ी न हो सकती।

श्री अ० प्र० जैन: मैं ने कहा था कि देर लगती ।

श्री बजराज सिंह : लेकिन उन के खुद के वक्तव्य से पता लगता है कि निर्यात के लिए उन्हें कोई मशीनरी नहीं खड़ी करनी पड़ी और वह काम एसोसियेशन कर रही है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि १९५७ में उन्होंने १,५३,००० टन चीनी बाहर भेजी थी और उन्होंने बार बार कहा है कि इस विषय में उनको जो अनुभव प्राप्त हो चुका है, विदेशों में उनके जो सम्पर्क स्थापित हो चुके हैं, उन को कायम रखने के लिए भी चीनी का निर्यात किया जाना चाहिए । मेरी समझ में नहीं आता कि जब इंडियन शुगर मिल्ज ऐसोसियेशन को चीनी के निर्यात का काम दिया गया, तो फिर किसी मशीनरी के कायम करने की जरूरत क्या आ पड़ी ।

श्री अ० प्र० जैन मैं ने यह नहीं कहा कि हम ने मशीनरी कायम की।

श्री बजराज सिंह : आप ने यह कहा है कि चूंकि मशीनरी कायम करनी थी, इसलिए जून में आर्डिनेंस पास करना पड़ा और अगर अगस्त में लोक-सभा के अधिवेशन के बाद यहां पर यह बिल रखा जाता, तो वह मशीनरी कायम करने में देर लग जाती और परिणामस्वरूप एक्सपोर्ट में भी देर हो जाती । खाद्य मंत्री की यह दलील कि आर्डिनेंस का पास करना जून में आवश्यक था, कोई अर्थ नहीं रखता है । उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, उन से पता लगता है कि जो कुछ चीनी बाहर भेजी गई वह १२, १३ अगस्त को तत्सम्बन्धी उत्तर दिए जाने के बाद बाहर भेजी गई । अभी तक सोलह, सत्रह हजार टन का सौदा—कंट्रेक्ट—हो चुका है, लेकिन कोई चीनी बाहर नहीं भेजी जा सकी है, क्यों कि जैसा कि माननीय खाद्य मंत्री ने स्वयं कहा है, इस में कुछ देर लगती है । लेकिन मेरा कहना यह है कि जब लोक-सभा का अधिवेशन शुरू हुआ, तब तक एक औंस भी चीनी बाहर नहीं भेजी गई और एक पाई फारेन एक्स-

चेंज की आप को नहीं मिली । जिस वक्त लोक-सभा का अधिवेशन नहीं हो रहा था, उस समय इस आर्डिनेंस के लागू करने से यह भावना फैली कि देश में चीनी की कमी हो सकती है और चीनी के मिल-मालिकों ने इस भावना का फ़ायदा उठाया, इस से कोई इन्कार नहीं कर सकता है । आंकड़ों में फ़र्क हो सकता है । मैं सिर्फ़ अन्दाज दे रहा हूं । आप ने कुछ चीनी फ्री सेल के लिए—बाजार में बेचने के लिए—रिलीज की । जब से यह भावना फैलाई गई कि चीनी का निर्यात किया जा रहा है, तब से मिल मालिकों ने भाव बढ़ने के परिणामस्वरूप साढ़े तीन करोड़ से कम मुनाफ़ा नहीं कमाया है । तब २८ रुपये और कुछ आने शुगर की कीमत थी और जो टैक्स बढ़ाया गया, उस को सम्मिलित कर, कुल मिला कर ३४, ३४-८-० से ज्यादा नहीं बैठती । जो और प्राफिट हुआ, उसको अतिरिक्त मुनाफा माना जा सकता है । उस सब को हमें जोड़ना पड़ेगा । इसी लिए मैं खाद्य मन्त्री के इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं कि वह इस सारे मामले को टैरिफ कमीशन के सुपुर्द कर दें, लेकिन वह कमीशन न सिर्फ यह देखे कि चीनी के उत्पादन का खर्चा क्या है, बल्कि यह भी देखे कि गन्ने के उत्पादन का क्या खर्चा है और किसान को जितना मुनाफा होना चाहिए, क्या वह वाकई हो रहा है या नहीं । खाद्य मंत्री यह भी देखें कि गन्ने की जो कीमत है, वह क्या वाकई इतनी है, जिस से किसान को जायज मुनाफ़ा मिल रहा है । अगर नहीं है, तो उस को भी टैरिफ़ कमीशन के सुपुर्द किया जाय और अगर उस की रिपोर्ट आने के बाद पता चले कि गन्ने की कीमत उतनी नहीं है, तो मैं आशा करूंगा कि सरकार गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए तैयार होगी ।

मैं समझता हूं कि जब लोक-सभा का अधिवेशन नहीं चल रहा था तो आर्डिनेंस प्रख्यापित नहीं किया जाना चाहिये था और न ही इसकी कोई आवश्यकता थी । उस वक्त इस को प्रख्यापित करके हमने अनावश्यक रूप से बाजार में चीनी की कमी की भावना फैलाई जिसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लोगों को मुनाफ़ा करने का अनुचित मौका मिल गया । इस मुनाफ़ाखोरी को रोका जा सकता था

16.12 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

लेकिन रोका नहीं गया । इसको रोक करके हम उपभोक्ताओं की रक्षा कर सकते थे और उस मुनाफे का और कुछ नहीं तो कम से कम जो गन्ने के उत्पादक हैं उनको लाभ पहुंचा सकते थे और उनका भला कर सकते थे । लेकिन उनका भला न करके इस मुनाफ़े को हमने चीनी के मिल मालिकों की जेबों में जाने दिया । यह उचित नहीं था ।

माननीय खाद्य मंत्री जी ने बताया कि जो अतिरिक्त प्राफिट्स होते हैं उनको एक और दो के अनुपात में बांटा जाता है । लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि अतिरिक्त मुनाफ़े के बटवारे की बात तो कर दी जाती है लेकिन गन्ने का जो रुपया बकाया है किसानों का करोड़ों की तादाद में, उसको उन्हें दिलवाने की कोई कोशिश नहीं की जाती है । इन अतिरिक्त मुनाफ़ों को कब दिया गया है कैसे दिया गया है या दिया जाता है, यह भी समझ में नहीं आता है । सन १९५२-५३ और १९५३-५४ में जो अतिरिक्त मुनाफ़े किये गये हैं उनके बारे में भी अभी तक झगड़े पड़े हुये हैं और अभी तक भी उनको उनका हिस्सा नहीं दिया गया है और कभी दिया जायगा भी या नहीं कुछ पता नहीं । यह सब हिसाब लगाने के बाद होगा और वह भविष्य के गर्भ की बात है । अगर दो

[श्री बजराज सिंह]

और एक के अनुपात में दिया जाता है, तो दिया जाय लेकिन यह अवश्य देखा जाये कि उनको उनका हिस्सा अवश्य मिले । मेरी समझ में यह दो और एक के अनुपात की बात भी नहीं आई है । आप दो रुपये और ७५ नये पैसे जो सेल होती है सो रुपये पर शुगर फैक्ट्री को देते है और उसमें जो किसान के गन्ने का खर्चा होता है वह करीब ४० प्रतिशत जा कर बैठता है । ऐसी सूरत में दो और एक के अनुपात की बात समझ में नहीं आती है । अगर कोई मुनाफा होता है तो वह भी इसी अनुपात से दिया जाना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि जो आर्डिनेंस जारी किया गया है यह अनुचित ढंग से जारी किया गया है और इसके कारण बाजार में बनावटी कमी पैदा की गई जिसका नतीजा यह हुआ कि उपभोक्ताओं को खास तौर से नुक्सान उठाना पड़ा । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इस आर्डिनेन्स को नामंजूर कर दिया जाए ।

अन्त में मैं एक और बात कहना चाहता हूं । मैंने शुरू में ही कहा था कि विदेशी विनिमय के अर्जन के लिए हमें यदि किसी चीज को बाहर भेजने की आवश्यकता पड़े, तो उसको बाहर भेजने में हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए । इसलिए मैंने कहा था कि इसका भी मैं स्वागत कर सकता हूं । लेकिन अपने मुल्क में उस चीज की क्या कीमत है और विदेशों में क्या कीमत है, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि ५०,००० टन चीनी के निर्यात से आपको एक करोड़ ५४ लाख रुपये के करीब एक्साइज ड्यूटी का नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी तरह से और भी नुकसान सहना होगा और इस के साथ ही साथ यहां पर भी चीनी के भाव में एक रुपया या सवा रुपया मन वृद्धि करनी होगी । जब ऐसी बात है तो यह सोचने पर हम विवश हो जाते हैं कि क्या चीनी का ही निर्यात किया जाए और उसी से सवा दो करोड़ या ढ़ाई करोड़ का विदेशी विनिमय पैदा किया जाए या विदेशी विनिमय पैदा करने के लिये और कुछ तरीके भी अपनाये जायें । मैं इस बात से सहमत हूं कि जो पुराने तरीके चले आ रहे हैं ज्यूट का टैक्सटाइल या चाय को एक्सपोर्ट करने के, इन से काम नहीं चल सकते हैं और इसलिए हमें नए तरीके सोचने चाहिये । लेकिन चीनी को बाहर भेजने का ही एक मात्र तरीका नहीं है । चीनी के निर्यात का सवाल इसलिए पैदा हुआ कि जो शुगर मैगनेट्स हैं वे यह समझते हैं कि २५ लाख टन जो उनकी चीनी पैदा करने की शक्ति है उतना पैदा करके वे उसको यहां खपा नहीं पायेंगे जिसका नतीजा यह हो सकता है कि कीमतें कम हो जायें । इसलिए बार बार निर्यात की बात करके वे अपने मुनाफों को कायम रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई उनके मुनाफे की बात न कर पावे । बाहर के मुल्कों में चीनी की कितनी खपत है और वहां पर पर-कैपिटा खपत क्या है तथा यहां क्या है, यदि इसका हिसाब लगाया जाए तो हमें खपत को यहां पर बढ़ाना होगा । लेकिन मिल मालिकों के सामने खपत को बढ़ाने का तो कोई सवाल ही नहीं है । उनकी ख्वाहिश तो यही है कि उनको ज्यादा मुनाफा मिले, फिर चाहे चीनी का निर्यात ही क्यों न करना पड़े अथवा किसी तरह से बनावटी कमी ही क्यों न दिखानी प

वे इन सब बातों के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसी दशा में मैं समझता हूं कि आर्डिनेन्स की तो कतई कोई आवश्यकता नहीं थी । जहां तक इस बिल के स्वागत करने का सवाल है अगर उस से विदेशी विनिमय पैदा होता है तो उसका स्वागत किया जाएगा लेकिन हमें भविष्य का भी खयाल रखना होगा । कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से आज गेहूं में तेजी आ रही है उसके कारण लोग अपनी जमीन में गेहूं बोना न शुरू कर दें और यदि ऐसा हुआ तो गन्ने का उत्पादन कम हो जाएगा और जब गन्ने का उत्पादन कम हो जाएगा तो चीनी के उत्पादन में कमी आ जाएगी जिसका नतीजा यह होगा कि चीनी का संकट पैदा हो जाएगा और जब चीनी का संकट पैदा हो जाएगा तो फिर मिल मालिक उस से अनुचित लाभ उठाने लग जायेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "This House disapproves of the Sugar Export Promotion Ordinance, 1958 (Ordinance No 5 of 1958) promulgated by the President on the 27th June, 1958"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the Bill to provide for the export of sugar in the public interest and for the levy and collection in certain circumstances of an additional duty of excise on sugar produced in India, be taken into consideration"

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The House will now take up clause-by-clause consideration.

Clause 2.—

(Definitions)

Mr. Deputy-Speaker: There are no amendments to clause 2. The question is:

> "That clause 2 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3.—

(Export Agency)

Shri Tangamani: I beg to move:

> Page 2, *after* line 25, *add*—
>
> "(3) The Central Government may cancel the appointment of any export agency by giving a month's notice and the same order shall be final"

Mr. Deputy-Speaker: The amendment is before the House.

Shri Tangamani: I shall explain the purpose of this amendment. In clause 2, "export agency" is defined as follows

> "'export agency' means any such agency as may be specified in this behalf under section 3, and when no such agency has been so specified, the Central Government"

So, under this definition, the Central Government itself is the export agency Where the Central Government do not export on their own, they nominate certain export agencies. Clause 3 deals with such export agencies.

Clause 3 gives more or less wide powers to the Government for appointing such agencies In the course of the first reading of the Bill, the hon Minister pointed out that one such agency has been appointed and that is the Indian Sugar Mills Association The Indian Sugar Mills Association have already exported with the help of the Government of India to the tune of 1½ lakhs tons in the year 1957. This year also I understand that they have already made

[Shri Tangamani]

arrangements and entered into agreements for the export of 12,400 tons, out of the target of 50,000 tons that has been fixed. In other words, there has been a monopoly created for a particular unit.

Now, this Indian Sugar Mills Association is also an organisation associated with or allied to the various sugar mills. As the House is aware, the sugar mills are more or less confined to some 7 or 8 concerns. In the south, we have the Parrys and in Bihar, Punjab and U.P., we have the Birlas, the Dalmias and others. These people have combined into one organisation, and through this legislation we are giving absolute power to this particular organisation. I would have been happier if the amendment which was given notice of by Shri Guha, amendment No. 3, had been accepted. That amendment says that the Government will nominate the State Trading Corporation. Where they do not nominate the State Trading Corporation, Government will have the power to appoint an export agency. If that provision had been there, that would have made clear the intention of the Government. My fear is that if the clause is allowed to stand as it is, this particular agency which has been appointed will continue as export agency for an endless period. My amendment, if it is read with the sub-clauses, will show that if we do not agree with the particular agency, Government will cancel that export agency by giving one month's notice, and the export agency will not have the right of appeal to any higher authority. The order of the Government cancelling this export agency will be the final order. Sub-clause (1), if it is strictly construed, will give power to appoint the State Trading Corporation. Many hon. Members of this House have expressed their desire that the S.T.C., which is already doing a lot of business in other industries, must be allowed to do this business. The explanation given by the hon. Minister is that the S.T.C. is full up; but that does not meet my argument.

My amendment only says that the power must vest with the Government. Government can nominate the S.T.C. If S.T.C. is not in a position to do that work, Government can appoint an export agency. But, as soon as the Government feels that this particular export agency must be cancelled, they must have the power to give one month's notice and complete the cancellation.

I would like to know from the hon. Minister whether any other export agency has made any offer and whether Government has any proposal to appoint anybody else as the export agency. Or, are they going to continue the present agency, as they have done in the past? This is a very serious matter. A monopoly has grown in the sugar industry, which we have protected for the last 25 years. The mill owners have profited themselves at the expense of the consumers. They have always been exporting sugar at their own sweet will and pleasure. Now we are giving a certificate to this particular monopoly to export this with the help and guidance of the Government. What will be the result? The result will be that we will lose Rs. 2½ crores or more, and this loss is going to fall upon the consumers. As the consumer prices are likely to go up and as the consumers have to make sacrifices, Government should not allow a particular export agency to function without any limit. With these observations, I propose that my amendment to clause (3) may be accepted.

Shri A. P. Jain: I have no difference with the hon. Member insofar as he wants that the Government should have the power to change the agency if it misbehaves. Now, according to the law, the authority which has the power to appoint has also the power to cancel. That need not specifically be provided in the section. Government will have the power to cancel the agency, if it misbehaves.

Shri Tangamani: Why can't we put it specifically in the clause?

Mr. Deputy-Speaker: It is generally understood that the appointing authority has always the power to cancel.

Shri Tangamani: He has got the right of appeal.

Mr. Deputy-Speaker: No question of appeal. The appointing authority can always cancel that, whatever institution it might be.

The question is:

"Page 2, *after* line 25, *add*—

"(3) The Central Government may cancel the appointment of any export agency by giving a month's notice and the same order shall be final"

The motion was negatived

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 3 stands part of the Bill"

The motion was adopted

Clause 3 was added to the Bill

Clause 4.—

(Fixation of quantity of sugar for purposes of export)

Shri Tangamani: I beg to move:

(1) 2,—after line 34, *add*—

"(d) the price trend prevailing in the sugar market."

(2) Page 2, line 37,—

for "twenty per cent." *substitute* "fifteen per cent."

My amendments deal with the blanket powers of the export agency. Clause (4) says that the Government will fix the quantity of sugar which may be exported and in fixing the quantity they will consider, the quantity of sugar available the quantity of sugar which will be required for consumption, the necessity for exporting sugar with a view to earning foreign exchange and so on. There I want to add "the price trend prevailing in the sugar market". That is my first amendment.

Now, clause 4(2) reads as follows:

"The power conferred by sub-section (1) shall be so exercised as to ensure that the quantity fixed under that sub-section for any year does not exceed in the aggregate twenty per cent. of the quantity of sugar produced in India in the season ending with the month of October falling within that year."

In my amendment I want to suggest that the percentage should be "fifteen" instead of "twenty". Already enough has been said about the quantity of sugar that is now produced in the country During the last ten years the production has doubled—from one million it has gone to two million. But consumption has also increased. The consumption during the current year, according to the Government figures, is 19 lakhs. By the end of the Second Plan period it may be more than two million—it may even be 25 lakhs, 23 lakhs according to the figures given in the Second Plan

It is true that export has been accepted Having accepted the principle of export, we must see that blanket power is not given for export. As production increases, several new factories would be coming up in several parts. Now the basis for fixing the quantity for export is the production in the last season. In the last season it was nearly two million tons. Now if 20 per cent is allowed for export, the exportable quantity will be four lakhs, though Government says it will be two lakh tons. When Government have a certain proposal for fixing the exportable quantity at two lakh tons, we must synchronise it with the percentage also. The amount must be the same according to the percentage also. So, ten per cent will be proper. But I have suggested fifteen per cent, instead of the present twenty per cent,

[Shri Tangamani]

which is exorbitant Because, that will give an incentive for more and more export Now, if we accept the percentage, it will be 4 lakh tons this year, 5 lakh tons next year 6 lakh tons year after and so on That is the point which I would like to bring to the notice of the hon Minister

While fixing the quantity for export you must also take into account the interest of the consumers here also Because though the price trend given to us is Rs 36-38 the prevailing consumer price is nearly Rs 45 per maund, at the rate of Rs 1-4-0 per seer, it will be Rs 45 per maund So, instead of the ex-factory price instead of the price which has been fixed by the Government the prevailing retail price should also be taken into consideration Already the fact that export is going to be allowed so far as sugar is concerned has given an upward trend to the prevailing price The hon Minister said that the prices have gone down That is a matter which we have to verify because when we left about three weeks ago the trend was upward, the price per seer was really going up And now the hon Minister says the price has come down If this 20 per cent is fixed, my fear is that the price will go up still further

The Deputy Minister of Food and Agriculture (Shri A M Thomas) Can you verify it only after you get back?

Shri Tangamani It can be verified To make it more real I was telling the hon Minister the price that was prevailing from my own experience in a particular market and if necessary the hon Minister and I could go round *incognito* and find out what the prevailing retail price is and he will also bear me out if the retail price at which it is sold in the market in Delhi works out to Rs 45

Mr. Deputy-Speaker The fear is both of them would be recognised, discovered

Shri Tangamani Both are coming from the South He is coming from one part I am coming from another part There is very little chance

Anyway the point is that in spite of the assurance given by the hon Minister there is no relation at all to the prevailing retail price today That is my submission So, this prevailing trend in the price also must be one of the criteria

Mr Deputy-Speaker The amendments to clause 4 are before the House

श्री ब्रजराज सिंह उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक के क्लाज ४ सब क्लाज ३ में लिखा है :—

"(2) The power conferred by sub-section (1) shall be so exercised as to ensure that the quantity fixed under that sub-section for any year does not exceed in the aggregate twenty percent of the quantity of sugar produced in India in the season ending with the month of October falling within that year"

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि दो सीजन होते हैं। एक अक्तूबर में खत्म होता है और दूसरा अप्रैल तक चलता है। इस में इयर की डेफिनिशन में कहा गया है 'दि इयर बिगिनिंग आन दि फर्स्ट डे आफ मे'। सो एक इयर में जिस में ३१ अक्तूबर तक सीजन खत्म होता है "विद दि मन्थ आफ अक्टूबर" उस में जितनी चीनी पैदा होगी उस का ज्यादा से ज्यादा २० परसेन्ट तक भेज सकते हैं। अब अगर आप हिन्दुस्तान में चीनी जो पैदा होती है उस के सीजन का हिसाब लगायें तो इस सीजन में बहुत कम चीनी पैदा होती है। बिफोर फोर्थ अक्टूबर सिर्फ ७ मास इंडिया मिलें चल रही थीं और बिटवीन फोर्थ अक्टूबर

और ३१ अक्तूबर ५ मिलें चल रही थी और इस तरीके से इस बीच में कोई मिल चलती नहीं है तो मुझे यह खतरा है कि इसका कानूनी फ़ायदा कहीं बीच में यह न उठा लिया जाय, मिल-मालिक फ़ायदा न उठायें कि हम से तो इस सीज़न में जो पैदा हुआ है उसका २० परसेंट ले लें। ५० हज़ार टन जो ले रहे है उस में पूरा फायदा मिलेगा अगर सीज़न का हिसाब लगाया गया इसर की डेफ़िनिशन के साथ। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो आपकी मंशा है मंशा शायद यह है कि जितनी पैदावार हो उसका २० परसेंट देंगी, आप बाहर भेज सकते है भेजें कम लेकिन कानून आपको यह अधिकार देता हो।

इन शब्दों का कानून में आगे यह अर्थ लगाया जायेगा कि जो सीज़न अक्तूबर में खत्म हुआ। साल शुरू होता है पहली मई से और अक्तूबर तक जो चीनी पैदा हुई उसकी सिर्फ़ २० परसेंट चीनी दे सकेंगे जिसके कि मानी यह होंगे कि कुछ भी नहीं मिलेगी। अगर भविष्य में वे यह सोचें कि इस में सरकार के साथ सहयोग नहीं करना चाहिए तब यह "सीज़न" की जो डेफिनिशन दी गई है वह गड़बड़ी पैदा कर सकती है। इस लिए ज़रा इस पर ध्यान दिया जाय कि कहीं लोग इसका कानूनी अर्थ वह न निकालें जो कि मैंने आपको बताया है।

Shri Naushir Bharucha: I only want to ask a question Power has been taken to determine the quantity. Why is it that power has not been taken for prescribing the quality and grade also?

Shri A. P. Jain: First I will deal with the two formal amendments.

Regarding amendment No. 6, you will kindly observe that one of the factors to be taken into account is "the quantity of sugar which, in its opinion, would be reasonably required for consumption in India." That by itself involves consideration of prices, not only the past but also the future, and therefore the intention of this amendment is inherent and I would not like to prescribe it as any special condition.

Regarding amendment No. 7, Shri Tangamani wants 20 per cent to be reduced to 15 per cent. He gave notice of another amendment which he has not moved to the effect that 20 per cent may be raised to 25 per cent.

Shri Tangamani: No, no. That is to the next clause. I will explain

Shri A P Jain: The amendment says "The export quota so fixed shall not exceed twenty-five per cent of previous season's production." It appears he is allergic to 20. He would either have it as 15 or 25

Mr. Deputy Speaker: There is no amendment.

Shri Tangamani: That has nothing to do with the amendment . Let the hon. Minister go through the list of amendments.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order If there is a mistake or misapprehension, we can correct it. Under clause 4 there is no other amendment except 6 and 7. Perhaps there is some misapprehension

Shri A. P. Jain: There is no amendment to that, but the fact is that either he wants to have it at 15 or 25.

Mr. Deputy-Speaker: Where is that 25 per cent amendment?

Shri A. P. Jain: Page 3, line 8.—

Mr. Deputy-Speaker: That is amendment to clause 5.

Shri A. P. Jain: He says that the export quota so fixed shall not exceed twenty-five per cent. of previous season's production. That is, each factory can be called upon to give up

[Shri A. P. Jain]

to 25 per cent. In the aggregate it will mean 25 per cent. At any rate, let us leave it at that.

Mr. Deputy-Speaker: The clause is different.

Shri A. P. Jain: The clause is different, but the fact is that it is contradictory. That is my contention. At any rate, I would like to maintain it at 20 per cent. We have fixed a very reasonable figure.

Two other points have been raised, one by Shri Braj Raj Singh

Mr. Deputy-Speaker: He says the season might create some trouble.

Shri A. P. Jain: We have given thought to it, and I do not think it is going to create any trouble, because we propose to declare quotas from November onwards, because then we shall be able to judge the prospects of the coming season, and it is in the light.

Mr. Deputy-Speaker: Is the season intended or the year?

Shri A. P. Jain: The season is what I am talking about

Mr. Deputy-Speaker: Then his apprehensions may be just

Shri Braj Raj Singh: The year has been defined as meaning the year beginning on the first day of May

Shri A. P. Jain: "Year" means from the 1st May until 30th April next year.

Mr. Deputy-Speaker: And season?

Shri A. P. Jain: And season means the production year ending on 31st October.

Mr. Deputy-Speaker: When does it begin?

Shri A. P. Jain: It begins on 1st November.

Shri Braj Raj Singh: Then it will not be within that year.

Shri A. P. Jain: There are two things. The year we have defined for the purpose of exports; the other is the production season. Now it is only after the month of October that we are in a position to assess.

Mr. Deputy-Speaker: Then this season means 12 months, not the year that is intended elsewhere. This also means 12 months.

Shri A. P. Jain: One is the season which is defined as beginning with the 1st November

Mr. Deputy-Speaker: Shri Braj Raj Singh says there are two seasons.

Shri A. P. Jain: There is only one season, there are not two seasons.

Mr. Deputy-Speaker: He might make sure

Shri A. P. Jain: I am quite sure about it

Shri Braj Raj Singh: Falling within that year, and the year is defined as beginning on the first day of May.

Shri A. P. Jain: Now the basis for fixation of the quota is the production of last year, but the export will take place in the following year, just as in the case of income-tax. So, while we will fix the quota on the basis of the production of the last season, i.e., 1st November to 31st October, the export will take place in the year which is defined here as commencing from 1st May and lasting till 30th April And so we will fix the quota only after making an assessment of the prospects of the coming season At any rate, I am certain there is no difficulty about it

Regarding Shri Bharucha's question, all the sugar factories are not manufacturing all the qualities of sugar Some are manufacturing some qualities of sugar, others are manufacturing other qualities of sugar Some of these qualities are popular in the foreign market and they can be exported. Others cannot be exported Therefore the exporting agency will

have the right to requisition a particular quantity, but it will not necessarily be the quantity which is the same quality in all the cases. Therefore there is a provision that wherever sugar is procured which is not popular in the foreign market will be sold internally.

Mr. Deputy-Speaker: I shall put amendments 6 and 7 to the vote of the House.

The question is:

Page 2,—

after line 34, *add*—

"(d) the price trend prevailing in the sugar market."

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 2, line 37,—

for "twenty per cent." *substitute* "fifteen per cent."

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 4 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5.— (*Export quotas for factories*)

Mr. Deputy-Speaker: Are there any amendments?

Shri Tangamani: Sir, I beg to move:

Page 3, line 8, *add* at the end—

"The export quota so fixed shall not exceed twenty-five per cent. of previous season's production."

I would not have said a word about this amendment, but for the observations of the hon. Minister. Clause 5 says that after having fixed 20 per cent of the last season's production in the whole country the Government will export the quantity so fixed. Now, this clause deals with individual factories. My amendment is that if we go to the individual factories in taking away something for export quota, it should not exceed 25 per cent of last year's production. It does not mean that you must go to every factory and get 25 per cent to make this 20 per cent. That was not the intention. In certain factories it may be necessary for going in and fixing the export quota.

The point raised by my hon friend, Shri Bharucha, will be very relevant and pertinent. We would like to have that type of quality and grade which is required for export. So, in taking the quantity available from that particular factory, it should not exceed 25 per cent. That is the purpose of this amendment. I would not have explained it but for the fact that the hon. Minister tried to misinterpret it.

Mr. Deputy-Speaker: Amendment moved:

Page 3, line 8, *add* at the end—

"The export quota so fixed shall not exceed twenty-five per cent. of previous season's production."

Shri A. P. Jain: The scheme is a fixed one. It is that the all-India quota will be fixed for export and that this all-India quota will be distributed equally in between all the factories according to the ratio which the production of the particular factory bears with the total production. There is going to be no variation. Now, therefore supposing if 5 per cent is realised then it will be 5 per cent of the production of each of the factories. Therefore, there cannot be any variation. 20 per cent cannot go up to 25 per cent. Therefore, I am sorry that I cannot accept the amendment.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

Page 3, line 8, *add* at the end—

"The export quota so fixed shall not exceed twenty-five per cent. of previous season's production".

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clauses 6 and 7 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 6 and 7 were added to the Bill.

Clause 8.— (*Sale by export agency of sugar delivered*)

Mr. Deputy-Speaker: Are there any amendments?

Shri Tangamani: Sir, I beg to move

Page 4, for lines 16 to 19, *substitute*—

"(2) For the purposes of sub-section (1) the export agency may sell the whole or any part of the export quota in its custody at a price approved by the Central Government where the export agency is not the Central Government"

Clause 8 has two sub-clauses. This gives power to the export agency to take all practical measures to export sugar delivered to it under this Act. But the proviso says that if the export agency is of opinion that having regard to the quality of the sugar delivered to it by any owner, or to the expenses involved etc., where they consider it expedient to do so, the export agency may sell the whole or any part of the sugar in India and may purchase such quantity of sugar as it may consider necessary for export at the appropriate time. This proviso gives powers to the export agency to sell the quantity that has come into their hands in the local market. That gives more or less an omnibus power. Sub-clause (2) gives more or less complete power to the export agency to dispose of this. I want sub-clause (2) to be deleted and in the place of that sub-clause, I want this to be substituted, namely:

"(2) For the purpose of sub-section (1) the export agency may sell the whole or any part of the export quota in its custody at a price approved by the Central Government where the export agency is not the Central Government"

Here it gives power to the export agency to sell it at a price approved by it. I want the powers to be exercised by the export agency for selling it at a price fixed by the Government. Where the Central Government is the export agency, the question does not arise. Where the export agency is an agency which has been created under clause 3, namely, in this particular case, the Indian Sugar Mills Association, the Indian Sugar Mills Association will not have complete power to sell it. The power to sell it is more or less delegated to the Government.

In this connection, I would also like to say that in this period, the price of sugar bears absolutely no relation to the increase in production or the increased consumption or the efforts put in by the agriculturist. I would like to mention that the agriculturist was getting probably Rs. 1-4-0 or Rs. 1-3-0 in 1947, per maund—even Rs. 2—and he is getting Rs. 1-5-0. The consumption price in those days as fixed by the Government was somewhere about Rs. 28-8-0 in 1949. Now, the price, according to the hon. Minister is Rs. 38. Consumption price has gone up. The ex-mill price has gone up. The price of sugarcane has come down. Production has doubled. This is a very peculiar thing because, in spite of certain excises here and there, a big margin is going to the mill owners. That has been the set up in the past. Let us not encourage.....

An Hon. Member: What about rate of taxation?

Shri Tangamani: The rate of taxation is there. I mentioned the rate of taxation. The rate of taxation does not affect the grower. Whereas he was getting Rs. 2/-, if he is getting Rs. 1-5-0, it is not due to rate of taxation. It is due to some other reason In 1937, for the hon. Member's information I may say, the price per maund was Rs. 7/-. The price per maund, according to the Government, is Rs. 38/-, more than five times Four times increase is not due to the excise duty. Excise duty is there The price of sugarcane has been kept down and the margin of profit has been increasing. That has been the contention of the trade unions also The wages of the workers have not considerably gone up. A Wage Board has been set up and it is still dragging on. There is absolutely no difference between the wages which have been paid to the workers in 1949 and the wages paid to the workers in 1958. There is very little difference. In spite of that, the ex-mill price that is fixed has been considerably higher This is more or less the overall position and the overall situation of the sugar industry Let us not give additional powers to these monopolies which are now developing by giving them complete powers to fix a price and sell it in the local market when they have got the exportable surplus back again to them because they are not going to export it. This is, I submit, a blanket power which is given to the export agency. This sub-clause (2) has therefore to be deleted and I submit that in the place of that, my amendment No. 10 may be accepted.

Mr. Deputy-Speaker: The amendment is before the House.

Shri A. P. Jain: Sub-clause (2) relates to sugar which has been requisitioned and which is not being exported either because of transport difficulties —the factory may be situated at a far distant place—or the particular grade is not popular. The sale and purchase operations where the quota has been fixed by the Government are to be done by this agency. I do not see why they should make any variation. In fact, this sugar will be sold in the open market either by the export agency itself or it may authorise the supplier to sell it at a specified price. I do not think that Government should come into it.

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put amendment No 10 to vote.

The question is:

Page 4,—

for lines 16 to 19, *substitute*—

"(2) For the purposes of sub-section (1) the export agency may sell the whole or any part of the export quota in its custody at a price approved by the Central Government where the export agency is not the Central Government"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That clause 8 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 8 was added to the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Now, we come to clause 9. Amendment No. 11 is not going to be moved, since Shri A. C. Guha is not here. So, I shall put all the other clauses together to vote.

The question is:

"That clauses 9 to 14, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 9 to 14, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri A. P. Jain: I beg to move:

"That the Bill be passed".

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill be passed".

If hon. Members agree to sit for another fifteen minutes, I can give five

[Mr Deputy Speaker]

minutes each to two or three Members who want to speak

श्री यादव (बाराबंकी) उपाध्यक्ष महोदय, अब बहुत थोड़ा समय रह गया है । जिस अध्यादेश पर हम लोग विचार कर रहे थे वह अब कानून की शक्ल अख्तियार करने जा रहा है और इस से उपभोक्ताओं और गन्ना उत्पादकों पर जो संकट आने वाला है उस पर आज सदन की पक्की मोहर लगने वाली है ।

उपाध्यक्ष महोदय अब भी रोक सकते हैं ।

श्री यादव जहां तक अध्यादेश का प्रश्न है मंत्री महोदय और उस तरफ के लोगों की ओर से कहा गया है कि इस तरफ के लोग सदैव अध्यादेश का विरोध करते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि कोई अध्यादेश किसी अच्छे कार्य के लिए हो और उस के लागू करने से कोई अच्छा नतीजा निकले तो इस तरफ के लोग सदैव उसका स्वागत करेंगे । माननीय मंत्री महोदय को याद होगा कि जब पत्रकारों के सम्बन्ध में एक अध्यादेश इस सदन में बिल की शक्ल में आया, तो इस तरफ के लोगों ने हृदय से उस का स्वागत किया । इसलिए यह कहना कि हम लोग सदैव अध्यादेश का विरोध करते हैं सत्य नहीं है ।

जहां तक इस अध्यादेश का प्रश्न है, सरकार ने पचास हजार टन चीनी निर्यात कर के विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए इस को जारी किया, जिस में से अब तक केवल नौ हजार टन भेजी जा सकी है जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा है, इस अध्यादेश के पहले भी सिर्फ १,५०,००० टन चीनी बाहर भेजी गई । तो फिर यह समझ में नहीं आता कि इस अध्यादेश को जारी कर के सरकार कौन से उद्देश्य की पूर्ति करने जा रही है । इस अध्यादेश पर, जो कि अब एक विधेयक की शक्ल में सदन के सामने प्रस्तुत है, यदि हम नजर करें, तो हमें पता चलता है कि सरकार मिल-मालिकों को टैक्स में कुछ छूट देने जा रही है । इस तरह जो नुकसान होगा, उस को और बाहर चीनी निर्यात करने में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, उस को सामने रखें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई बड़ा लाभ होने वाला नहीं है । विदेशी मुद्रा की प्राप्ति के लिए अनेक जरिये हो सकते हैं । जैसे इस समय जो बहुत सी विलासिता की चीजों को विदेशों से मंगाया जा रहा है हम उन को रोक सकते हैं और इस प्रकार विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं लेकिन विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए चीनी को एक्सपोर्ट करने से मामूली नफा हो सकता है । उस से कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है । इस अध्यादेश का सीधा असर इस देश के उपभोक्ताओं और गन्ने के उत्पादकों पर पड़ा है । चीनी के दाम बढ़ गए हैं । सरकार केवल विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिए चीनी को बाहर भेजना चाहती है लेकिन जब यह विधेयक कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा, तो वह उपभोक्ताओं और गन्ना उत्पादकों के लिए एक मुस्तकिल मुसीबत का बायस बन जायगा ।

माननीय मंत्री महोदय, और कृषि मंत्रालय ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं । अक्सर यह देखा जाता है कि जो आंकड़े और संख्यायें सदन के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं, वे बहुत ही गलत हुआ करते हैं ।

उस पर विश्वास करना और उन के आधार पर कोई काम करना ग़लती है। आज सरकार द्वारा जितनी भी स्कीमें चलती हैं, वे इन आंकड़ों के आधार पर होने की वजह से हर जगह असफल होती हैं। जो आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, वे सही नहीं होते हैं। चीनी के भाव के बारे में अगर हम शहरों के अलावा देहात की तरफ़ देखें, तो हमें मालूम होगा कि १-४-० रुपये के हिसाब से चीनी बिक रही है। यह समझना सही नहीं होगा कि केवल रीटेलर के यहां ये भाव बढ़े हैं। जब इस तरह से बाज़ार में भाव बढ़ते हैं, तो उस का असर मिल-मालिकों पर भी पड़ता है और वे लोग होल-सेलर से मिल कर अच्छा खासा मुनाफा कमाया करते हैं। इसलिए यह कहना गलत है कि भाव में कोई खास तेज़ी नहीं आई है।

जहां तक किसानों का प्रश्न है, उन की दो शक्लें हुआ करती हैं —एक तो वे गन्ना उत्पादक हैं और दूसरे वे उपभोक्ता भी हैं। इस लिए उन पर दोहरी चोट पड़ती है। जब वे उत्पादक होते हैं, तो उन से कम दाम पर गन्ना लिया जाता है और गन्ने को एक निश्चित मूल्य पर मिल-मालिकों से खरीदवाया जाता है। इस के बाद जब चीनी का भाव ३४ रुपये और ३६ रुपये से बढ़ कर ३८ रुपए और ४५ रुपए तक हो जाता है, तो उपभोक्ता के रूप में भी उन को नुक्सान उठाना पड़ता है। इस तरह उन को दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है।

मंत्री महोदय ने कहा कि गन्ने का भाव १-५-० और १-७-० रुपए है। दो आने तो ढुलाई है और उस को गन्ने के मूल्य में शामिल नहीं कर सकते हैं। इस में भी एक बड़ी एनामेली है। जब किसान मिल के गेट पर गन्ना देता है, तो उस को १-७-० रुपये मन दिया जाता है, लेकिन अगर वह किसी दूसरे केन्द्र में गन्ना दे, तो उस को १-५-० रुपया मिलता है, जब कि केन्द्रों पर भी किसानों को गन्ना कई मील दूर से लाना पड़ता है। जिस तरह मिल के गेट पर किसानों को बैल गाड़ियों पर गन्ना लाना पड़ता है, उसी तरह केन्द्रों में भी लाना पड़ता है। फिर न जाने गेट पर १-७-० रुपए और केन्द्र पर १-५-० रुपये क्यों दिया जाता है। जो दो आने मन ढुलाई की शक्ल में दिया जाता है, उस से मिल मालिकों को काफ़ी फायदा हुआ करता है। जब मंत्री महोदय इस तरह की बात किया करें तो वह मतलब भी समझा करें कि यह दो आने मन गन्ने की कीमत नहीं है।

जब गन्ने के दाम बढ़ाने की बात कही जाती है, तो मंत्री महोदय कहा करते हैं कि चीनी के उत्पादन का खर्च बढ़ गया है। केवल कुछ टैक्स के अलावा या किसी जगह मजदूरी के अलावा चीनी के उत्पादन का खर्च नहीं बढ़ा है, बल्कि गन्ना तो सस्ता ही मिलता है। इस के विपरीत किसान का खर्च बढ़ गया है। उस की सिंचाई की दर बढ़ गई है और मजदूरी भी बढ़ गई है। उस की तरफ मंत्री महोदय ध्यान नहीं देते हैं। इस स्थिति में गन्ने का दाम अवश्य बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से तो एक तरफ़ा कार्यवाही की जाती है।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह अध्यादेश कानून के रूप में आयेगा, तो उस की बकिन्या देखी जायेगी, लेकिन इस में कोई शक नहीं है कि इस से देश का, उपभोक्ताओं का या गन्ना उत्पादकों का हित नहीं होगा और न ही विदेशी मुद्रा की समुचित मात्रा में प्राप्ति होगी, जिस से सरकार को कोई फ़ायदा हो। इस से देश में एक ऐसा भाव पैदा होगा कि चीनी की कीमत बढ़ने लगी है। सरकार के पास ऐसी

[श्री यादव]

कोई मशीनरी नहीं है, जो दुकानों पर चीनी की बिक्री पर कुछ नियंत्रण रख सके । इसका परिणाम यह होगा कि स्थिति और भी गंभीर होती जायगी । मैं अब भी कहूंगा और मदन के विवेक से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित न होने दें ।

Shri Jhulan Sinha (Siwan): While I rise to support the passing of the Bill, I may just offer certain observations without attempting to answer the criticism levelled from the other side.

17 hrs.

I have been fortunate enough to see this country heavily importing sugar from outside draining away its resources only a few years ago Now, the country is in a position when we are thinking of exporting to the tune of 20 per cent of our production. There was a time, I clearly remember, when India and Pakistan were together—in undivided India—the whole country consumed only about 10 lakh tons of sugar Now, the position is that when we are producing about 20 lakh tons, some of us are eager not to allow even a maund of it to go out of the country, and we want to consume the whole thing ourselves It is fortunate that the country has been able to produce so much. But in the conditions through which the country is passing, the shortage of foreign exchange is a thing which we have to face. We have got to meet that and find ways and means for meeting it, whatever may be the cost to our own convenience or amenities. Therefore, while supporting this Bill which allows the export to the tune of 20 per cent, I will just draw the attention of Government to certain aspects of the problem which, I think, they should take into account and should never forget.

I am not very clear about this; I have not been able to follow how this Indian sugar which costs a lot more than sugar produced in other countries will be able to compete in the foreign market.

Then there is the case of the grower. The grower of sugarcane should not be forgotten. In our anxiety to export sugar and earn foreign exchange and to subsidise the export from this country, we are likely to forget the case of the producer. Therefore, at this last stage of the Bill I would just draw the pointed attention of Government to the case of the grower and to the case for the general development of this industry.

There are three aspects of the problem that have to be kept in mind. Government should never slacken their attempts to increase the yield per acre of sugarcane in this country. At the same time, the recovery percentage from sugarcane should also be heightened up The third thing I would like to urge is that the case of the cane growers should not be lost sight of

The cane growers are an unorganised body of kisans who have to face a body of highly intellectual and well organised people, the mill owners of this country Therefore, the case of growers is likely to be not given the same attention as it deserves

The price of sugarcane in this country has been varying from Rs. 2/- per md. to Rs. 1/5 to Rs. 1/7. Although the conditions have remained practically the same in this country—I am not going to blame anybody for this—the cane growers have now to be content with getting Rs. 1/7 per md. of cane while they used to get Rs. 2/- only some 3 or 4 years back. The cost of production and the prices of other things which the grower requires have been going up; and yet I do not know how the price of cane has been kept so low at the same level for the last 2 or 3 years. So, I would request the Government not to lose sight of the cane grower.

Shri A. P. Jain: I have nothing to add.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: The House now stands adjourned to meet again tomorrow at 11 o'clock

17.05 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 27th August, 1958.